colleague, Shri Jaswant Singh, for leave to withdraw the bill to declare the Indian Council of World Affairs to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and matters connected therewith, which was passed by the Lok Sabha on the 18th December, 2000, and laid on the Table of the Rajya Sabha on the 18th December, 2000.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI JAGMOHAN: Sir, I withdraw the Bill.

DISCUSSION ON THE STATEMENT OF PRIME MINISTER RECENT SUMMIT-LEVEL TALKS HELD BETWEEN INDIA AND PAKISTAN IN AGRA (Contd.)

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी (झारखंड) : शुक्रिया सदरे मोहतरम, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने आगरा चोटी कॉन्फ्रेंस जैसे अहम मौजू पर मुझे बोलने का मौका इनायत फरमाया है।

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश): चोटी पर?

†**मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी** : जी, शिखर वार्ता को उर्दू में चोटी कॉन्फ्रेंस कहते हैं। चोटी कॉन्फ्रेंस - आला सतहई कॉन्फ्रेंस। असल में अगर हर ज़ुबान का इस्तेमाल हो तो लोगों को अजनबियत महसूस नहीं होगी। ...(**व्यवधान**)... सदरे मोहतरम, हमारे वज़ीरे आज़म हिन्द जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब और पाकिस्तान के हमारे वज़ीरे आज़म के तसलीमशुदा सदर जनाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ आगरा में जो सरबराह मुलाकात हुई, उस पर पार्लियामेंट में बहुत ही तफसील से चर्चा हो चुकी है। मैं चंद बातों की ओर आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा हूं। सदरे मोहतरम, हिन्दुस्तान एक मेज़बान मुल्क है और हिन्दुस्तान की मेज़बानी तारीखी रवायात की हामी है। दुनिया का सबसे पुराना मुल्क, दुनिया की सबसे कदीमी तहज़ीब, दुनिया का सबसे कदीमी मआशरा और दुनिया की सबसे कदीमी मेज़बानी की विरासत हिन्दुस्तान के मुकद्दर में आयी है। हमने अपनी उन्ही रवायतों को बरकरार रखते हुए पाकिस्तानी सदर जनाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की मेज़बानी के भी फरायज़ अंजाम दिये। माज़ी की बेशुमार तलखियां, नफरतों और वहशतों के दरमियान जिस तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की मेज़बानी के फरायज हिन्दुस्तान ने अंजाम दिये हैं, हिन्दुस्तान की इस वसी- उल -क़लबी और फराखदिली को सारी दुनिया में सराहा गया है। यकीनन ये हिन्दुस्तान के सायानेशान था, जो अपने दुश्मनों को भी मेहमान बनाए। आपने मेज़बानी के सारे रिकार्ड तोड़कर दुनिया में खुद अपनी मेजबानी का रिकार्ड कायम किया। मैं अपने मुल्क के तमाम शहरियों को इस अजीमुश्शान मेजबानी की मुबारकबाद देता हूं। सदरेमोहतरम, आगरा में किन मसायल को लेकर यह चोटी कांफ्रेंस हुई, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के आवाम के दिलो-दिमाग में बेपनाह गुंजाइश पैदा हो गई कि हम लोग आपस में मेल-जोल का एक माहौल देखने की सआदत हासिल

---

† Transliteration of the speech in Persian Script is available in the Hindi version of the debate.

करेंगे। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि हम कोई मुसतरका एजेंडा ऐलानिया की शक्ल में सामने नहीं ला सके और बातचीत को आला सतही और नाकामी से गुजरना पड़ा। क्योंकि हुकूमत के लोग कामयाबी मानते हैं, मगर सिर्फ नसिसतन गुफतन बर्खास्तन को कामयाबी माने। बैठिए, खाइए, पीजिए और चले जाइए अगर इसका नाम कामयाबी है तो यकीनन यह मुलाकात कामयाब रही। मगर मैं समझता हूं कि जिस एजेंडे पर, जिस मसले पर, जिस झगड़े पर मुलाकात तय हुई थी अगर वह मसला तय नहीं हुआ तो हम इस मुलाकात को कामयाब मुलाकात कहने से गुरेज करेंगे। मसला क्या था, सदरे पाकिस्तान सिर्फ मसला-ए-कश्मीर को लेकर यहां आए थे। यह कोई छुपी हुई बात नहीं थी, यह छपी हुई बात थी। यहां आने से पहले उन्होंने दो टूक अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार कर दिया था। यहां आने के बाद भी उन्होंने दो टूक अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया। हमारी प्रैस ने भी कहा, हुकूमत के कुछ जिम्मेदारान की तरफ से भी बात आई, जनरल परवेज मुशर्रफ सियासी आदमी नहीं है, सोल्जर हैं, फौजी आफिसर हैं, इसलिए इस सियासी बसीरत से महरूम हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर एक जनरल सोल्जर है, सियासी बसीरत से मेहरूम है और एक मसले पर टिका और अड़ा हुआ है तो हम तो सियासी बसीरत से मेहरूम नहीं हैं। हम तो अपनी सियासी बसीरत का लोहा सारी दुनिया से मनवा चुके हैं। अगर जनरल परवेज मुशर्रफ सिर्फ मसला-ए-कश्मीर पर अड़े हुए थे तो हमारे पास इतनी गुंजाइश थी कि हमें मसला-ए-कश्मीर पर भी जमकर बात करने की पॉजिशन मे थे। अगर वे हिन्दुस्तान के कश्मीर को मुतनाजिया कश्मीर कह रहे थे तो हमें पाकिस्तान के पास रहने वाले कश्मीर को भी अपना अटूट हिस्सा कहते हुए उनसे वापसी का मुतालबा करना चाहिए था। मगर हमारा ये कहना है कि कश्मीर भी एक मसला है और भी सारे मसायल पर बात करेंगे तो क्या हम आपसे यह अर्ज करना चाहेंगे कि झगड़ा तो पूरी दुनिया में मसला-ए-कश्मीर पर हमारे सामने है। एक बात हमारी समझ में नहीं आती कि जब कश्मीर हमारा अटूट अंग है तो उनसे बात करने की भी क्या जरूरत थी। उनको दो टके का जवाब देकर भेज देना चाहिए था कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है। मैं कहता हूं कि क्या जम्मू पर हम पाकिस्तान से डिबेट करते, क्या पंजाब पर पाकिस्तान से डिबेट करते, क्या बिहार और यूपी पर पाकिस्तान से हम डिबेट करते? क्या हिन्दुस्तान के दीगर 24 सूबों पर हम पाकिस्तान से डिबेट करते? पाकिस्तान या दुनिया की किसी ताकत से हम डिबेट करते? इसलिए कि सारी दुनिया जानती है कि यह हमारा अटूट हिस्सा है? इसी तरह कश्मीर का हम रुबावर कराने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? कश्मीर भी हमारा वैसा ही अटूट हिस्सा है जैसा दिल्ली हमारा अटूट हिस्सा है। जिस तरह पंजाब और महाराष्ट्र हमारे अटूट हिस्से हैं...

श्री टी. एन. चतुर्वेदी (उत्तर प्रदेश) : कुलदीप जी को जरा बता दीजिए।

†**मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी** : आप बताइएगा। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कश्मीर पर भी अगर वे बात करके जाना चाहते तो हमें कश्मीर पर भी बात करनी चाहिए थी मगर कहने का मतलब यह है कि वे मुजाहिदीन आजादी दूसरों को कहते रहते हैं, आतंकवाद फैलाने वाले, टेरेरिज्म करने वालों को मासूम शहरियों की जान लेने वालों को, अपने मुल्क की आजादी का एक हिस्सा कहते रहे और उसकी तुलना मुक्तिवाहिनी से करके चले गए। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जनरल परदेज मुशर्रफ साहिब के एक प्रोग्राम में अगर उन्होंने किसी सियासी बसीरत का सुबूत नही दिया तो हमें जरूर अपने सियासी बसीरत का सुबूत देना चाहिए था।

† Transliteration of the speech in Persian Script is available in the Hindi version of the debate.

जनरल की सदारत का वजीर-ए- आजम हिन्द की तरफ से खैर मकदम दरअसल जनरल को इन्टरनेशनल हीरो बनाने का मुतरादिफ था। जिस माहौल में हमने उनसे बात की है उसमें एक तरफ तो हम जम्हूरियत की कद्रों की पामाली के बारे में सारी दुनिया में ढिंढोरा पीटते हैं और दूसरी तरफ हमारी ही पुश्त पर जम्हूरियत का कत्लेआम हुआ। जम्हूरियत के दो नुमाइंदे पाकिस्तान में थे एक का नाम बेनजीर भुट्टो है दूसरे का नाम मियां नवाज शरीफ है। चुनी हुई हुकूमतों को जिस तरह से वहां बर्खास्त किया जाता है, जिस तरह से उन ममालिक के हुक्मरानों को दर-बदर फिराया जाता है और शहरबदर किया जाता है ऐसे कैरेक्टर के आदमी ने जिस वक्त ग़ासबाना तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत पर कब्जा किया उसकी ग़ासबाना सदारत को तसलीम करने वाला दुनिया का कोई मुल्क नहीं था। इत्तफाक और बदनसीबी की बात है कि हमारी गवर्नमेंट थी और हमारे हिंदुस्तान के वजीरेआजम थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी लचर पॉलिसी से मसला-ए-कश्मीर कैसे हल होगा? हम इससे पहले भी कह चुके थे, जब निचली सतह पर बातचीत हो रही थी तब भी हमने कह दिया था कि बातचीत का दरवाजा उस वक्त खुलेगा जब बॉर्डर पर क्रास टेरेरिज्म खत्म हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आगरा चोटी कांफ्रेंस के मौके पर क्रास बॉर्डर टेरेरिज्म खत्म हो गया था? क्या पाकिस्तानी आतंकवादियों को शह नहीं मिल रही थी? क्या वे कश्मीर में तोड़-फोड़ नहीं कर रहे थे जनरल मुशर्रफ के रहने के वक्त भी और जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद भी? जिस तरह आदमियत का खून बहाया गया है और कश्मीर में इंसानियत की कद्रों को पामाल किया गया है क्या यह सारी दुनिया नहीं देख रही है? क्या इस चीज को हमारा मुल्क नहीं जानता है? एक मर्तबा हिंदुस्तान की सौ करोड़ की आबादी और पूरी दुनिया के इंसानों को इस एत्माद में लेना कि पाकिस्तान टेरेरिज्म फैला रहा है और जब तक टेरेरिज्म खत्म नहीं होगा उससे बातचीत का कोई सवाल पैदा नहीं होता लेकिन यकायक नजरेसानी करने की जरूरत भी नहीं समझी गई और आगरा चोटी कांफ्रेंस का ऐलान करके सारी दुनिया को चौंका दिया गया। यह कौन सी हुकूमत की पॉलिसी है कि एक तरफ तो कहते हो कि उस वक्त तक बात नहीं करेंगे जब तक टेरेरिज्म खत्म नहीं होगा तो क्या उस वक्त टेरेरिज्म खत्म हो गया था जब आप लोगों ने आगरा में ताजमहल का सपना देखा था? मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इस मसले पर आपने संजीदगी से गौर नहीं किया। इस मसले पर संजीदगी के साथ पूरे आवाम को ऐत्माद में लेकर कोई गुफ्तगू नहीं की गई वरना पाकिस्तान से मामला क्या है। हम बोली के जरिए यह मामला हल करना चाहते हैं और पाकिस्तान गोली के जरिये यह मसला हल करना चाहता है किसे इस बात से इंकार हो सकता है। हमारी कूटनीति और राजनीति के बहुत चर्चे हैं। हम सारी दुनिया को यह भी बावर नहीं करा सके कि पाकिस्तान एक टेरेरिस्ट मुल्क है और इसे टेरेरिस्ट मुल्क घोषित किया जाना चाहिए, इसे टेरेरिस्ट मुल्क करार दिया जाना चाहिए तो हम किस कूटनीति और किस पॉलिसी की बात करते हैं। पाकिस्तान हमारी छाती पर मूंग दल रहा है, बारह साल से मुसलसल हमले पर हमले करता जा रहा है, हमारे नौजवानों का कत्लेआम, हमारे बच्चों को यतीम, हमारी औरतों को बेवा और हमारी बहिनों की मांग का सिंदूर खुरचता चला जा रहा है। इसके बावजूद वह कौन सी हमारी कूटनीति की कामयाबी है, कौन सी राजनीति की कामयाबी है कि हमने सारी दुनिया को बावर करा दिया कि पाकिस्तान एक टेरेरिस्ट मुल्क है। हम उस वक्त कामयाब होते जब सारी दुनिया को हम यह बावर कराते कि वह टेरेरिस्ट मुल्क है, उसे टेरेरिस्ट मुल्क करार दिया जाए, वह वहशत का नकीब है वह दरिंदगी का नुमांइदा है। मगर अफसोस की बात यह है कि हुकूमत की नाकारा पॉलिसी की बुनियाद पर आज तक हम दुनिया को यह बावर कराने में कामयाब नहीं हो सके।

सदरेमोहतरम, एक बात और अर्ज करने की कोशिश करूंगा बारह साल से कश्मीरी आवाम की हालत-ए-जार पर भी जरा नजर डाल लें। उन्हें तो हमने मुर्ग मुसल्लम खिलाया वे चले गए। उन पर करोड़ो रुपया खर्च किया, सेहत तक का खयाल रखा गया, डॉक्टर साथ में रखे गए लेकिन हमारे वे फौजी जिन्हें उनके फौजी और सिपाही निशाना बनाते हैं उनकी जान और माल के लिए तहफ्फुज के लिए हमने कुर्बानियों से कोई दरेग नहीं किया। मगर सदरे मोहतरम, पत्थर पर दूब नहीं जमती, दूब तो गीली जमीन पर उगती है। बंजर जमीन से अनाज उगाने का ख्वाब देखना अहमकों की जन्नत में रहना है। दूब अच्छी जगहों से उगती है, अच्छी जगहों से फसले लहलहाती हैं। पाकिस्तान से इस बात की उम्मीद करना कि बातचीत के जरिए हम मसला-ए-कश्मीर को हल कर लेंगे एक दीवाने के ख्वाब के अलावा मुझे और कुछ दिखलाई नहीं देता। हुकूमते हिंद को सख्त जुबान में पाकिस्तान से बात करने की जरूरत है। मैं एक बात और अर्ज करना चाहूंगा कि हुकूमत का जब यह मुअक्कफ था कि जब तक टेरेरिज्म खत्म नहीं होगा बात नहीं करेंगे लेकिन इसके बावजूद हुकूमत अपने मुअक्कफ से हट गई और घुटना टेक सरकार बनकर पाकिस्तान के सामने झुकती दिखलाई दी। मैं यह कहना चाहूंगा कि अब जब पाकिस्तान बुला रहा है तो यह कह दें कि हम घुटनाटेक सरकार नहीं हैं। अब तो वाकई जब तक टेरेरिज्म खत्म नहीं होगा पाकिस्तान की धरती पर किसी तरह का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। इसलिए कि यह किसी मुल्क की इज्जत का सवाल है, यह किसी पार्टी की इज्जत का सवाल नहीं है। यह हिंदुस्तानी कौमी यक-जहती का सवाल है, यह किसी पार्टी के मिनिस्टर और किसी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर का सवाल नहीं है। सदरेमोहतरम मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि तीसरी ताकत के मुदाखलत से भी इंकार किया गया। मगर प्रेस के जरिए यह पता चला, मीडिया के दिगर जराए से यह पता चला, खुद हुकूमतों की इशारतन और किनायतन गुफ्तगू से यह पता चला कि कहीं न कहीं दाल में काला है। कोई माशूक है इस पर्दे ए जंगारी में, किसी माशूक ने इसका इंतजाम करवाया था। जो आगरा की चोटी की कांफ्रेस हुई, मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ साफ साफ हम कहते हैं कि किसी दूसरे का हस्तक्षेप हम नहीं चाहते। लेकिन दूसरी तरफ अब धीरे धीरे यह बादल छंटने लगे हैं और तीसरी ताकत का चेहरा भी निगाहों के सामने आने लगा है कि कौन तीसरी ताकत है, जो कभी हमें झुकवा कर बात करवाती है और कभी उन्हें झुकवा कर बात करवाती है। इसलिए मै गुजारिश करूंगा कि हिन्दुस्तान का नजरिया बहुत साफ होना चाहिए। हमें नर्वस सिस्टम का शिकार नहीं होना चाहिए। हमारा मुल्क दुनिया का वह ताकतवर मुल्क है जो मादनियात और माशी बुनियाद पर ताकत नहीं रखता बल्कि वह अखलाखी बुनियाद पर ताकत रखता है, इल्मी बुनियाद पर ताकत रखता है, अमली बुनियाद पर ताकत रखता है। तहजीब की ताकत यह कोई मामूली ताकत नहीं है, विरासतों की ताकत कोई मामूली ताकत नहीं है, रिवायात की ताकत कोई मामूली ताकत नहीं है, मेजवानी की ताकत कोई मामूली ताकत नहीं है, तमाम धर्मों को मिलाकर चलने वाली ताकत का इत्तिहाद कोई मामूली ताकत नहीं है। हिन्दू का "ह" और मुस्लिम का "म" मिलकर हम हैं। मुत्तेहदा कुब्बत बनकर उभरने वाले हिन्दुस्तान की ताकत मामूली ताकत नहीं है। इस ताकत को दूसरों को एक्सप्लाइट नहीं करने देना चाहिए। हमें खुले दिमाग से साफ सुथरी नीति बनाकर पाकिस्तान से बात करते हुए अपनी एक इंच जमीन पर भी पाकिस्तान को ख्वाब देखने का तस्सवुर नहीं देना चाहिए। मैं तो अभी सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस चोटी की कांफ्रेंस में वजीरे आजम को सिर्फ एक शेर पेश करके अपनी बात खत्म करता हूं :

उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें,
लुट गया हो जो मुसाफिर जा के मंजिल के करीब।

थैंक यू, शुक्रिया।

MR. CHAIRMAN: There are a number of speakers. I would like the speakers to be brief. Now, Shri J. Chitharanjan; you have nine minutes, because your Party has nine minutes.

SHRI J. CHITHARANJAN (Kerala): Hon. Chairman, Sir, the Communist Party of India, which I represent, had welcomed the initiative taken by the Prime Minister of India to invite Mr. Musharraf, the President of Pakistan for Summit-level talks. It is so because we believed that the disputes between the countries will have to be settled through negotiations. Resorting to the tactics of settling the disputes through force will be very dangerous and disastrous. That is why we had supported that initiative. Sir, at the same time, we thought that the Government might have done some preparations before the start of the Summit. The Summit-level talks between the Heads of States is quite different from the talks at the official level, at the level of Secretaries or even at the Ministerial level. It being so, Sir, a careful and serious preparation will have to be made, while we arrange for Summit-level talks. At several levels, discussions should have been carried on, at the official level, at the Ministerial level, etc. just to explore or probe the mind of the other party, to understand what perspective they are having and also to understand whether there is any amount of agreement that could be reached. But, to my surprise, the Government has failed in that. It was a very serious mistake on the part of the Government of not having done such a serious preparation. Now, the Summit had ended, and we could neither arrive at a minimum settlement, nor we could come out with a joint declaration. Even then we are of the view that we will have to continue the dialogue. There is no other way to solve the problems between the two countries.

At the same time, I would like to point out that the Prime Minister had stated: "We made progress despite differences in our perspectives. We made progress towards bridging the approaches in the draft joint document." So, if you go through what he said in his statement, you will find that both the parties were having different perspectives. While Gen. Musharraf was asking to focus on Kashmir and had even gone to the extent of stating that without Kashmir no other issue could be discussed, the Government of India was taking the position that we should have a

composite dialogue. In the same manner, when we demanded that there was a question of stopping the cross-border terrorism, he refused to agree. Not only that, he even went to the extent of characterising it as a freedom struggle. I do not want to go into it in more detail, but what I would like to point out is that there was an ocean of difference between the two parties. In such a situation, how can you arrive at conclusion that there was a possibility of bridging the approaches in a draft joint document? If this is correct and if what the Prime Minister has stated here is also correct, then something more, which has not been revealed here, might have taken place during the discussions and we have been kept in dark on that point. Otherwise, there is no meaning in saying that there was a possibility of bridging the gap in our approaches.

My next point is that the spokesman of the Government had repeatedly said that we will proceed on the basis of the Simla and Lahore agreements. After the Summit, we had even gone to the extent of saying that we will not start our further discussions on the basis of Agra talks. We will begin afresh from Simla and Lahore Agreements. At the same time, Shrimati Sushma Swaraj, while speaking yesterday said: Unlike in the settlements in Tashkent and Simla, we have not surrendered our interests. We have come out with a fixed deposit. Kindly see what is their attitude regarding the Tashkent Agreement and the Simla Agreement. If it is the opinion of the Government that the Tashkent Agreement and the Simla Agreement were a surrender, then why should they say that they will proceed on the basis of the Simla Agreement, and not on the basis of the Agra talks? Therefore, I would like to say that the spokesman of the Government has been taking different positions with regard to these things. Its manifestations are different and here also during the discussions here, the Government has manifested itself differently.

Now, I come to another point.

Of course, on the Agra Summit, there were differences on almost all the issues. On this Summit, opinions are being expressed as to why should we talk or have a dialogue with Pakistan. Some sections of the ruling party, especially the major party in the NDA, have expressed the view that in the present conditions when Pakistan is taking such an attitude, we should not continue dialogue with them. Some people even went to the extent of saying that we should prove that we are strong enough to face any situation created by Pakistan. What do they mean by that? A basic

question arises in our mind. Should we continue this dialogue with a view to bringing about a settlement on Kashmir and other disputes? According to me, the dialogue should continue.

Regarding the Kashmir issue, we will have to deal with Pakistan. We will have to face terrorists. We all know that for the last three years, especially, the Home Minister has been repeatedly making statements that we will put an end to terrorist activities with an iron hand and we would suppress it.

MR. CHAIRMAN: You have taken ten minutes.

SHRI J. CHITHARANJAN: I am concluding, Sir.

On the one side, we are making toll promises. On the other, killings of ordinary people are going on. Therefore, we will have to check this. Another thing which I would like to point out is, it is necessary for us to win over the confidence of the people in Kashmir. I am of the opinion that we have not succeeded in this. To some extent, they are alienated from us. Why did it happen? We will have to examine it. There is an article -- article 370 in our Constitution. What is our attitude towards it? Are we standing by that? On the basis of this article, are we prepared to have a talk with those who are in power in Kashmir and arrive at a reasonable understanding? I do not know whether the Government is initiating such an action. Therefore, I request the Government to ensure that the people of Kashmir are won over. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Now, Mr. Kuldip Nayyar. I would like to inform the hon. Members that we have about 15 speakers on this discussion. The list of speakers is to be completed today. The Prime Minister would reply on Monday, 13th August after the Question Hour. If the House agrees, we will sit through lunch hour and continue with this discussion. After the Private Members' Business is over, we will resume the discussion.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

SHRI SURESH PACHOURI (Madhya Pradesh) : Yes, Sir. Today, we can finish the discussion by skipping lunch hour so that on Monday, the Prime Minister can reply to the debate.

SHRI KULDIP NAYYAR (Nominated): Mr. Chairman, Sir, I don't think that the Agra Summit has failed. The very fact that both the leaders

Shri Atal Bihari Vajpayee, Prime Minister of India and Gen. Musharraf met, I think, that itself was an achievement. And the fact that they are going to meet in future whether at the United Nations or later, I think, is a plus point.

Where, I think, the Government has failed is, in not properly communicating to the media what was going on. Where is that declaration or statement that Jaswant Singhji said was written in Punjabi English and he initialled it? Maybe it was Rajasthani English! I think the Foreign Affairs Office did not handle the media properly. Communication is an art. You can formulate a policy, the best of policies. But, if you are not able to pervade, if you are not able to convey it, then, what is the use?

Now, the Foreign Affairs Minister and the Prime Minister have said certain things, some were here, some were outside, some were at the various BJP meetings. I wish this had been known to us earlier. What has happened is, since these things were not available to us, we have written on the basis of certain things which were inferred or which we heard. It is true that, now, some other opinion is being created. But I can tell you, with all humility, to Jaswantji, that the impression which we have created, wrongly or rightly, is going to stay with the people because printed word is very much honoured and respected here. I think the failure of the Government has been not to take the people into confidence or at least not to tell us what was happening, which they have done now.

[The Deputy Chairman in the Chair]

I have been following this subject for many years. I have come to this conclusion that I do not think that the two Governments are going to solve this problem. I think this problem of Kashmir is not a territorial problem. This is an ideological problem; ideological, in the sense that Pakistan insists on having the Valley, and that is only because it is Muslim populated. I remember, when I was with Atalji in that bus to Lahore, there was a breakfast given to Sardar Prakash Singh Badal, the Punjab Chief Minister, by Nawaz Sharief. He suggested to him at the breakfast meeting, "Sardarji, you can take Ladakh, Buddhist, Jammu, Hindu, and give us the Valley, Muslim population, and that is the end of the matter." Sardarji Badal Saheb kept quiet. But I intervened and said, "Sir, you can take the whole Jammu and Kashmir. But this time, the criterion is not going to be religion. The basis of any type of settlement is not going to be religion because I have seen Partition. I have come through that." How many lakhs of people were killed? I hope that our External Affairs Minister and our Prime Minister

1.00 P.M.

must have conveyed to Pakistan that as far as this problem is concerned, it will never be settled on the basis of religion. Though, sometime, I wonder, because there are talks of trifurcation of the State, by the RSS or some other people. ...*(Interruption)*...

SHRI T. N. CHATURVEDI: Why do you bring in the RSS?

SHRI KULDIP NAYYAR: Some such organisation. They talk of trifurcation. To my mind, this matter can be settled in two ways.

Firstly, people to people contact must take place. I am glad that the Government of India has taken some steps which have eased the restrictions on visas. But, I am surprised that, while, Shri Jaswant Singh has taken so many steps, he has not lifted the ban on newspapers and books. Why don't you lift the ban on newspapers and books? You have done a good thing. You lift the ban unilaterally. Let their newspapers come here. Otherwise, these are being unloaded here and printed. Why do we have restrictions on newspapers and books? I hope the Minister will consider this thing seriously. When you meet the people in Pakistan, you will realise their compulsions. These people have been under martial law or some other kind of law for almost thirty years. Their society is not like our society. It is not like our open society. They are afraid to talk. So, we have to take some steps whereby we draw those people to our side. Some of us make an effort. But when we make an effort, we are misunderstood here, because, this is the usual line followed by the people on this side. Let the intelligentsia come, let doctors, lawyers, journalists and common men meet. That will generate some kind of goodwill, and all our problems will be easier to solve. When I am coming to the people, I am talking of the people of Jammu and Kashmir. We have made certain commitments to them. When Jammu and Kashmir joined the Union of India, certain promises were made. They acceded to us only three subjects, that is, Defence, Foreign Affairs and Communications. Over the years, that autonomy of theirs has been corroded. We have taken more powers. Through the Assembly or through the Governor, we have taken more subjects. I am of the opinion that we shall have to go back to the same position, and I do not agree with the Home Minister that we cannot go back to the pre-1953 position. I think, if we have to win the confidence of the people of Kashmir, we will have to go back to what they acceded to us. The Union has no right to say: " Look here, now, the time has passed. You cannot have it." After all, artilce 370 of

the Constitution assured this thing. Madam, one more point I want to make. I am very happy to know that the Prime Minister and the Foreign Affairs Minister have said again and again that we shall not tolerate cross-border militancy. I think, this is a correct stand, because, in the name of cross-border militancy, murders are being committed. Some mercenaries are coming, some fundamentalists are coming and killing the innocent people. I want that some intellectuals in Pakistan or some columnists in Pakistan should make an effort in this direction to find out how this situation is being communalised and how Hindus are being picked up and killed. I think, if those people are given the opportunity to speak, they will say so. But it is not happening because, they don't have that kind of freedom which exists here. *(Time Bell)* Madam, I speak very rarely, and here also, you are ringing the bell.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am ringing the bell because there are still some speakers, and Mr. Jaswant Singh will take the floor. ...*(Interruptions)*... When I am speaking, you must listen to me.

SHRI KULDIP NAYYAR: I am sorry.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have to make an announcement. I am not just speaking like that. The Minister has to speak at 1.30 P.M. So, I have to accommodate two, three other speakers. That is why I was trying to tell you this thing.

श्री कुलदीप नायर : मैडम आपने मेरा चेन ऑफ थॉट्स तोड़ दिया।

Let me make one more point. A criticism has been made of the Indian media, which is very unfair. When in Agra, for 34 hours, there was nothing, not a word from the External Affairs Ministry, what you people were doing, what the Press was doing.

After all, they are readers. They have their own audience. This is where the Ministry is to blame. But I have not been able to understand why the Prime Minister did not take the Indian editors into confidence. Indian editors could have talked to them before and after the talks. I recall, and I shall sit down, that Lal Bahadur Shastri was going to Tashkent. I happened to be his Press Secretary. He called the editors and placed all cards on the table. He took them into confidence because when it used to be Haji Pir Titwal, whether they would be given to Pakistan or not, he told them, and once he was not able to persuade them, he told them, "Today, there would be a pressure from the Soviet Union, and I may not be able to

do what you are saying." He explained it to them. I think, that way, he was able to take the people into confidence. Similarly, I wish this Government would be a little more transparent and take some people into confidence. After all, there are so many people amongst the journalists who belong to his party, or who are having the same point of view. Let those people be taken into confidence. At least, something should come out. Let me say, at the end, let us not leave this path of dialogue. I know it is very difficult. I know Pakistan being so intransigent that, probably, sometimes, you may lose patience, but, if we have a neighbour like this, we have to live with it, and we have to talk to it. The only thing is, let us stand on principles, let us stand on basics, and that is that we will not budge on the ideological point, and that we will not allow the cross-border militancy to go on. Thank you very much, Madam.

†**मिर्ज़ा अब्दुल रशीद (जम्मू और कश्मीर)** : मैडम डिप्टी चेयरमैन साहिबा, आगरा सम्मिट हो या कश्मीर पर डिस्कशन हो, बात कश्मीर के इर्द-गिर्द ही घूमती है। मैं अपनी बात शुरू करुंगा इस शेर के साथ कि :-

तू फकत देखता है साहिल के रज्म में खैरो-शर
कौन तूफां के तमाचे खा रहा है, मैं के तू?

इसमें कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट, संसद के ऑनरेबल मैम्बरान् वहां की जनता की हमदर्दी के लिए हुकूमत पे नुक्ताचीनी भी करते हैं और इनके दिल में दर्द भी है, लेकिन वहां खून के समंदर में कौन गोताज़न हैं, वे.जम्मू-कश्मीर के आवाम हैं।

इससे पहले कि मैं वहां की बातें आपके सामने रखूं, मैं मुबारक दूंगा जनाब वाजपेयी जी को जिनके तदब्बुर, जिनकी सियासत दूरंदेशी और तजुर्बाकारी ने मुशर्रफ को मज़ाकरात की दावत दी और यह दावत कमज़ोरी नहीं, यह सियासी तदब्बुर है। यह मजबूरी नहीं, यह अपने आप पर और अपने देश की ताकत पर ऐतमाद है। यह कोई फौजी मसला नहीं, यह सियासी मसला है और यहां हमारे एक्स सी.एम.सी., जनरल मलिक ने भी कहा कि यह मसला सियासी है। आज का मौजूदा जनरल भी यही कहता है कि सियासी मसले को सियासी तौर पर हल किया जाता है।

जिनके रुतबे बड़े होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं। इसलिए हमारे प्रधान मंत्री ने बड़े तदब्बुर से, बड़े हिम्मत और हौसले से कदम उठाकर यह जो कांफ्रेंस की, इसके पीछे भी हमारे देश का इतिहास है और जैसे मौलाना साहब ने फरमाया कि हमारे देश का इतिहास है कि हम नान वायलैंस का दर्स देते हैं, दया, धर्म और इंसानियत का दर्स देते हैं, जीयो और जीने दो का सबक सिखाते हैं हमारा मुल्क भी कुछ ऐसे ढंग से बना है कि -

सरजमीने हिंद पे इकवामे आलम के फराक,
काफिले आते रहे हिन्दोस्तां बनता रहा।

---

† Transliteration of the speech in Persian Script is available in the Hindi version of the debate.

वाजपेयी जी ने बड़े भाई का बड़े वकार से रोल अदा किया, जनरल को सदर बनाया और पहली बार 50 सालों में एक पाकिस्तानी सदर को राजघाट ले गए, दुश्मनी के दायरे से खींचकर दोस्ती के दायरे में लाए और कारगिल के हमलावर को आगरा की पीस-टॉक्स में बातचीत करने के लिए बुलाया, दरवाजा खोलकर उनको बुलाया मगर उनके अड़ियल रवैये के कारण, उनकी हठधर्मी और जिद के कारण उनको खाली हाथ जाना पड़ा। जाते हुए उनके जजबात यह हो सकते हैं, मुशर्रफ साहब के जजबात ये हो सकते हैं कि मेरे दिल में मोहब्बत करवटें लेती रही, लेकिन मैं उस नफरत का क्या करता जो अपने साथ लाया था।

महोदया, इस सिलसिले में मैं तो यूं कहूंगा कि इतिहास में नफरत को बदलने के लिए, दुश्मनी की दीवारों को तोड़ने के लिए दोस्ती का कभी-कभी मौका मिलता है और हमें खुशी है कि यह दरवाजा खुला है आने-जाने का और हमने उस दरवाजे को खुला रखा है गुडविल मिशन के लिए, कॉन्फिडेंस बनाने के लिए।

महोदया, भारत और पाकिस्तान के बीच अगर कोई सबसे बड़ा मसला है तो वह आपसी विश्वास का मसला है। इसको हासिल करने के लिए कभी-कभी मुखालफत के कड़वे अलफाज़ भी बरदाश्त करने पड़ते हैं तनाव कम करने के लिए। यह लंबी दौड़ है, लंबा मसला है वह इसलिए कि इन 50 सालों के लंबे समय में जो मुश्किलें सामने आई हैं उनको हल करने की जरूरत है। इतनी लंबी दौड़ में फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में कामयाबी या नाकामयाबी को किसी हार या जीत के तराजू में नहीं तोला जा सकता। हां, यह बात जरूर है कि -

कदम चूम लेती है खुद आकर मंजिल,
मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे।

और वह हिम्मत हमारे प्राईम-मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर में मौजूद है। मैं यहां सिर्फ दो-तीन बातें आपसे गुज़ारिश करूंगा। जसवंत जी यहां तशरीफ रखते हैं, ये बड़े कंपीटेंट, बड़े मुदब्बर फॉरेन मिनिस्टर हैं लेकिन अभी मुशर्रफ साहब का दिल इस मोहब्बत के काबिल नहीं था क्योंकि -

मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मख़सूस होते हैं,
ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता।

महोदया, इस बारे में मैं यह कहूंगा कि वो आए और भारत की झोली में बैठकर इस प्रॉक्सी वॉर को ऐलाने-जंग करार देकर चले गए, टैररिस्ट्स को फ्रीडम-फाइटर्स का रुतबा देकर चले गए। इसी तरीके से जो बेगुनाह और मासूम औरतें और बच्चे हलाक होते हैं, उनको तारीख-ए-आज़ादी के ज़माने की कुर्बानियों की तस्वीर देकर चले गए। कश्मीर को वे अनफिनिश्ड अजेंडा करार देकर चले गए। इसी के साथ वे यह भी कहकर चले गए कि कारगिल की जंग जो थी, वह बंगलादेश का बदला था।

महोदया, इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं यह कहूंगा कि ऐडीटर्स कान्फ्रेंस में उन्होंने दो-कौमी थ्योरी को फिर जिंदा करने की कोशिश की और इसके साथ-साथ यह जो सैपरेटिस्ट ताकतें हमारी रियासत में थीं और जो हमारे यहां सैपरेटिस्ट मूवमेंट है, उसको ताकत देने के लिए उन्होंने काफी कोशिश की। तो सबसे बड़ा काम उन्होंने यह किया कि सारे हिंदुस्तान की जनता को ठेस पहुंचाई, उनके जजबात जख्मी किए और इस तरह वे जम्मू-कश्मीर सरकार को और वहां की अवाम को एक बड़ा चैलेंज देकर चले गए और दिल्ली की सरकार को भी इतना बड़ा चैलेंज देकर चले गए।

महोदया, जम्मू-कश्मीर में जो हमारी रियासत है, उसमें सदियों से सेक्यूलरिज्म की विरासत रही है और शेख-उल-आलम से लेकर लल्ला अरफा, बड़शाह से लेकर शेरे-कश्मीर तक सदियों पुरानी जो हमारी विरासत रही है, उसे ऋषियों, मुनियों, भक्तों, शायरों और अदीबों ने कायम किया है। इसीलिए 1947 में जब मुल्क आज़ाद हुआ तो उस ज़माने में शेरे-कश्मीर के समय में वहां एक मच्छर तक नहीं मरा जब कि पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हर जगह इंसानियत और आदमियत हिंसा की आग में झुलस रही थी। अब उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान साजिशें कर रहा है, हमले कर रहा है। वहां कभी चिरारेशरीफ को आग लगा रहा है, कभी हजरत बल में हमले कर रहा है, कभी अमरनाथ और वैष्णो देवी में पहरे बैठाने के लिए हमें मजबूर कर रहा है। इन सब बातों के बावजूद जो हमें अफसोस है वह इस बात का है कि धरती हमारी, यह लोग हमारे और यह सरहदें हमारी और पाकिस्तान इंसानियत के खून से इस धरती को रंगीन बना रहा है। इसका हमें बड़ा अफसोस है। हम इनसे पूछना चाहते हैं और अपनी सरकार से पूछना चाहते हैं कि यह मोर्टर कहां से आते हैं, यह तोप कहां से आती है और यह पाकिस्तानी लोग कैसे पहुंचते हैं ऐसा हमें वहां के लोग पूछते हैं। हमें वहां के लोग यह भी पूछते हैं कि यह आर.डी.एक्स. के अम्बार वहां से कैसे आते हैं और फौजी पाकिस्तानी कैसे आते हैं, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। हम अपनी दिल्ली की सरकार से पूछना चाहते हैं कि इसका जवाब हमको दीजिए कि हम उनको क्या कहें। जबकि यह डिफेंस के पास मामला है। वह कहते हैं कि वहां से अगर यह लोग नहीं आएं तो यहां मिलिटेंसी है ही नहीं। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, मुझे एक बात कहने की इजाजत दीजिए कि इसमें कोई शक नहीं कि वहां जद्दीपुरा में अगर सरदारों को इजतमाई तौर पर शहीद किया जाता है, कत्ल किया जाता है, कश्मीर में बेबस पंडितों को अगर इजतमाई तौर पर खत्म किया जाता है, डोडा में या अमरनाथ में कत्ल-दर-कत्ल गोलियों से उनके सीने जख्मी किए जाते हैं उनको खत्म किया जाता है, राजौरी व पुंछ में कोटचलवाल में 25 मुसलमानों को एक घर में झुलसाया जाता है, मंजरकोट में 25 मुसलमानों को एक ही दिन मारा जाता है, सुवरकोट मे बफलियाद में 50 मुसलमानों को मारा जाता है। कश्मीर में यह तबाही हो रही है तो वहां के लोग हमसे यह पूछते हैं जिस वक्त कोई अकलियती तबके का ग्रूप शहीद होता है उनको हलाकत होती है जिसकी हम बड़ी पुरजोर मज़म्मत करते हैं पाकिस्तान की। उस वक्त संसद में भी हंगामा होता है, मीडिया में भी इसकी चर्चा आती है, अखबार में भी आता है। लेकिन जब वहां के मुसलमानों को मारा जाता है तो कोई जिक्र नहीं होता। तो इसका बड़ा अफसोस है मैं हाउस में यह कहना चाहता हूं। आम अंदाजा है कि शायद 80 हजार लोग वहां मारे गए। चलो मान लीजिए कि 40 या 50 हजार ही मारे गए तो 50 हजार में से 5 हजार अकलियत तबके के लोग हैं और 45 हजार मजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं। तो वह कहते हैं कि मुसलमान या हिन्दू को नहीं मारते हैं वह तो हिन्दुस्तानी मारते हैं, यह तो इंसानियत मारते हैं। वह तवक्को रखते हैं पूरी कौम से और पूरे हाउस से कि जो भी मरे उसके लिए वह हमदर्दी जताएं और उनकी भी पूरी मदद करें और ऐसे ऐक्शन की पूरे तौर पर मज़म्मत करें। जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, यह तो 1947 में तय हो चुका है। 1947 में उस वक्त तय हो चुका था बल्कि 1947 से पहले 1936 में यह फैसला हो चुका था जब शेरे कश्मीर ने मुस्लिम कांफ्रेंस को नेशनल कांफ्रेंस में बदला था। शेरे कश्मीर ने जिन्ना साहब की टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया और महात्मा गांधी की जम्हूरियत को एक्सेप्ट किया है। शेरे कश्मीर ने लियाकत अली की ललकार को रिजेक्ट किया और जाहिदलाल की आवाज को पुकारा और यह दो कौमी थ्योरी तो उस वक्त से रिजेक्ट की है शेरे कश्मीर ने और इसलिए की है कि इसके पीछे एक

तारीख अब 1947 के बाद जब महाराजा हरीसिंह ने इलहाक़ किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन किया। अभी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे थे। तो उन्होंने तीन सब्जेक्ट इलहाक़ किया। यह आटॉनोमी जिसको हम आज कहते हैं, यह महाराजा जी ने दिल्ली से मांगी। महाराजा जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन किया, नेहरू जी ने उसको तसलीम किया, शेरे कश्मीर ने असेम्बली में उसको एप्रूव किया और सिर्फ एप्रूव ही नहीं किया बल्कि यूनाइटेड नेशंस में जाकर भी ताइद की और इस पर बयान दिया। आज अगर इसके बारे में वहां की इलेक्टेड असेम्बली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की निगरानी में इलेक्ट होती है वह एक रिजोल्यूशन भेजती है जो रद्दी की टोकरी की तरह रिजेक्ट किया जाता है। उसको बयान भी नहीं किया जाता, बहस भी नहीं की जाती, तो आप ही अंदाजा लगाइए कि आप एलिनेटेड आबादी को किस तरह से मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। हम आपसे यह सवाल पूछना चाहते हैं, जसवंत जी यहां तशरीफ रखते हैं, हम इनसे यह कहना चाहेंगे यह जो आटॉनोमी की रिपोर्ट है, आडवाणी जी बदस्तूर यह कहते आए हैं कि 353 नहीं दिया जाएगा। हम उनसे कहते हैं कि इसको हाउस में लाओ, इस पर बहस करो। पूरा हाउसकांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकिल-370 के तहत अगर इसमें कोई ऐसी क्लॉज है जो आज के दिन ऑब्जेक्शनेबिल है तो दोनों तरफ से एक्सपर्ट्स कमेटी बनाओ और अगर कोई आब्जेक्शनेबल है तो उसको प्रेस नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह जो वायदा है, यह जो प्रोमिस है इसको अगर वापस नहीं किया जायेगा तो जम्मू-कश्मीर की अक्सरियत को, अवाम को आप कैसे साथ में रखोगे, मैं इसका जवाब चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि जनाब जसवंत सिंह जी, प्रधान मंत्री जी अपनी जवाबी तकरीर में कम-से-कम इस हाउस में इस आटानॉमी पर बहस कराने के सिलसिले में और एक कांस्टीट्यूशनल एक्सपर्ट की कमेटी बनाने के सिलसिले में यह फरमायेंगे ताकि इसका वहां कुछ फायदा हो सके। ...(समय की घंटी)...

मैडम, मैं आपसे माफी चाहूंगा। मुझे कश्मीर पर बोलना है इसलिए चार-पांच मिनट का और समय दे दीजिए। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूं।

उपसभापति : कश्मीर के और लोगों के नाम भी है। शरीक साहब का नाम भी है।

†**मिर्जा अब्दुल रशीद** : मैडम, वह कल बोल चुके हैं किसी दूसरे विषय पर।

उपसभापति : उनका नाम भी लिखा है।

† **मिर्जा अब्दुल रशीद** : मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमें अफसोस इस बात का है कि इस वक्त भी जब कश्मीर में, हमारे यहां पिछली बार 1996 में इलेक्शन हुआ, जनाब आनरेबल फॉरेन मिनिस्टर साहब, उस इलेक्शन में पाकिस्तान ने कहा कि यह इलेक्शन नहीं है, यह रेफरेंडम है। अगर रेफरेंडम है तो उस वक्त पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी नवाज पार्टी थी उसने पाकिस्तान का झंडा "चांद और तारा" वाला अपने साथ में रखा, कुराने-करीम को अपने हाथ में रखा और पाकिस्तान के हक में वोट मांगने की कोशिश की हिन्दुस्तान के खिलाफ। लेकिन 50 साल के बाद भी जम्मू-कश्मीर की आवाम ने, अक्सरियत ने और मुसलमान तबके ने इसको रिजेक्ट किया। दूसरा वह तबका था कि जो आजादी चाहता था। वह आजादी के लिए जलूस निकाल रहा था, उन्होंने अपने कैंडीडेट्स खड़े किए और सब कैंडीडेट्स की जमानत जब्त हुई। लेकिन जम्मू-

† Transliteration of the speech in Persian Script is available in the Hindi version of the debate.

कश्मीर की आवाम नें आर्टिकल 370 के तहत आटोनॉमी के रेस्टोरेशन के वायदे के तहत फारुख साहब को 75 फीसदी वोट दिया और 75 फीसदी वोट देने के बाद आटोनॉमी का रिजोल्युशन आया। जिस वक्त तक यह रिजोल्युशन रिजेक्ट नहीं हुआ था। पाकिस्तान की नींद हराम हो चुकी थी, अगर यह रेस्टोरेशन वापस हो जाता तो यह मसला जिसका इंटरनेशनलाइजेशन हो चुका था वह डि-इंटरनेशनलाइजेशन हो सकता था। मैं यही अर्ज़ करूंगा अपनी मरकज़ी सरकार से कि इसको बड़ी गहराई से, बड़े गौर से और बड़ी हमदर्दी से देखा जाए। अगर आप कश्मीर की अक्सरियत आवाम को अपने साथ रखना चाहते हो तो आपको जरूर इसको रिव्यु करना होगा। हमारी बीजेपी सरकार के सारे लीडर साहिबान यहां पर बैठे हैं, हम इनके एनडीए में सपोंटर हैं और हर बार सपोर्ट करते हैं, खासकर हम वाजपेयी जी की सरकार को हर मौके पर सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें अफसोस है कि इन्हीं की पार्टी के एक लीडर जो जम्मू-कश्मीर में प्रेसीडेंट हैं वह बार-बार यह बयान दे रहे हैं कि फारुख साहब की सरकार को डिसमिस करो। यह कितने अफसोस की बात है। जहां तक डिसमिस करने की बात है तो मैं हाउस को याद कराना चाहता हूं कि 1953 में आपने शेर-ए-कश्मीर को डिसमिस किया, 1964 में आपने बक्शी साहब को डिसमिस किया, 1965 में आपने सैयद साहब को डिसमिस किया, 1975 में आप कासिम साहब को बरतरफ करके शेर-ए-कश्मीर को लाये, 1977 में आपने शेर-ए-कश्मीर को डिसमिस किया, 1983 में फारूख साहब चुनकर आये और आपने 1984 में फिर उनको डिसमिस किया और गुलशाह को लाये, 1986 में आपने गुलशाह को डिसमिस किया, 1987 में फारुख साहब चुनकर आये और 1990 में आपने फिर उनको डिसमिस किया। आज भी अगर आप डिसमिस करना चाहते हो तो आप डिसमिस कर दो। आप उनको डिसमिस क्यों करते हो आप पैगाम भेजिए उनको वह छोड़ देंगे। आप कश्मीर को सम्भाल लो। लेकिन अगर डिसमिस करने से आपका मसला हल हो सकता है तो उनको कोई एतराज नहीं होगा। वह चार बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं और उनको अब चीफ मिनिस्टर बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन उनकी कमिटमेंट है। उनकी कमिटमेंट यह है कि वह इस मुल्क की एकता की खातिर, वह महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू के उसूलों की खातिर अपनी जान हथेली पर रखकर पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। वह कारगिल से लेकर जेनेवा तक, श्रीनगर से लेकर यूएनओ तक भारत का साथ दे रहे हैं। इसीलिए मैं गुज़ारिश करूंगा कि इसी महीने फारुख साहब पर दो हमले हुये, उनके बेटे जो आपकी सरकार में मंत्री हैं, उन पर दो हमले हुए और बड़ी मुश्किल से बचे, हमारे शरीक साहब, एम.पी. भी उस हेलीकाप्टर में थे। पिछले महीने जिस वक्त मुशर्रफ साहब यहां आये थे तो रशीद शाही जो हमारे मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके सगे छोटे भाई को शहीद किया गया और इसी महीने में हमारे कादर साहब जो मिनिस्टर हैं उनके घर को उड़ाया गया, मियांबशीर के बेटे के पैर को उड़ाया गया। पिछली दफा गुलाम अहमद बट जो मिनिस्टर थे, उसके जिस्म के पुर्जे उड़ाए गये। कई एम.एल.ए., कई एम.एल.सी और कई वर्कर्स इस वक्त शहीद हो रहे हैं। पंचायत का इलैक्शन जो इस वक्त फारूख साहब ने किया है, पहले मरदुमशुमारी कराई, फिर पंचायत का इलैक्शन कराया, पूरे 14 जिलों में पंचायत का इलैक्शन हो चुका है। यह सारे पंचायत के इलैक्शन होने के बाद जो सरपंच बने, बहुत सारे सरपंचों को, बहसियत उमीदवार मीर साहब के भाई को उड़ा दिया, बनने के बाद उनको खत्म कर दिया। सरपंचों के अलावा किसी सरपंच का कान काटा, किसी का नाक काटा, किसी का जिस्म काटा। इतनी बड़ी जंग जम्मू-कश्मीर में फारूख अब्दुला साहब अपनी पार्टी की रोशनी में भारत के लिए लड़ रहे हैं, वह भारत की जंग कश्मीर में लड़ रहे हैं और फिर भी उनको कहा जाता है कि इनको डिसमिस करो। इस किस्म

की आवाजें वहां प्रो इंडिया फोर्सिज़ को कमजोर करती हैं और एंटी इंडिया फोर्सिज़ को सपोर्ट देती हैं। हम यह तवक्को रखेंगे कि इस किस्म की बातों को रोकने के ऐकदाम किए जाएं वरना पाकिस्तान की मजबूती सैपरेटिस्ट की मजबूती के बराबर होती है। जनाबे आला, एक बात मैं और कहना चाहता हूं। विश्व हिन्दू परिषद के कुछ साथी या दूसरे कुछ लोग शायद यह समझते हैं कि फारूख साहब शायद लैफ्ट-राइट, अपने ही लोगों से वहां हुकूमत कर रहे हैं इसलिए वे हमारी कोई बात नहीं मानते हैं। फारूख साहब चीफ मिनिस्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है लेकिल फारूख साहब के चीफ सैक्रेटरी दिल्ली के आई.ए.एस. ऑफिसर हैं, उनके डी.जी.पी. दिल्ली के आई.एफ.एस. ऑफिसर हैं, दो ऐडिश्नल डी.जी.पी. दिल्ली के आई.ए.एस. ऑफिसर हैं, उनके प्रिंसिपल सैक्रेटरी दिल्ली के आई.ए.एस. ऑफिसर हैं, चार जम्मू के आई.जी.पी. और चार कश्मीर के आई.जी.पी. दिल्ली के ऑफिसर हैं, 5-6 डी.आई.जी. हैं, वे भी दिल्ली के ऑफिसर हैं। 14 डिस्ट्रिक्ट्स में से 12 डिस्ट्रिक्ट्स में जो डिप्टी कमिश्नर हैं, वे भी हमारे यहां के आई.ए.एस. आफिसर्स हैं और जो एस.एस.पी. हैं, वे भी यहां के हैं, डिफैंस यहां का है, फाइनेंस यहां का है तो उनके पास क्या है? वे तो सिर्फ असूलों के लिए और कमिटमेंट्स के लिए देश की लड़ाई वहां लड़ रहे हैं, उसके बावजूद आज 14 में से 12 जिलों में ऐक्ट लागू करके आर्मी को अख्तियार दिये गये हैं। हम इस ऐक्ट के खिलाफ नहीं हैं, हम इसके हक में हैं। वह इसलिए कि पाकिस्तान ने जो इस वक्त हमला कर रखा है और खासकर मुशर्रफ ने यहां दिल्ली में आकर जो ऐलान-ए-जंग कर दिया है उसका मुकाबला करने के लिए - यह बार्डर पर जंग नहीं हो रही है, यह घर घर में ज़ंग है, यह मोहल्ले-मोहल्ले में जंग है, हर गली में जंग है। इस जंग का मुकाबला करने के लिए यह ऐक्ट लगाना बहुत जरूरी था ताकि वहां के लोग, वहां की हुकूमत और दिल्ली की सारी सरकार और सारा डिफैंस - सब मिलकर इसका मुकाबला करें। इसलिए हम इसकी मदद करते हैं, इसकी मुखालफत नहीं करते। अलबत्ता एक वार्निंग देना चाहते हैं कि अगर ऐसे माहौल में आर्मी के हाथों किसी बेगुनाह शक्स को मारा जाए या बेगुनाह शक्स को तकलीफ पहुंचे तो बजाय फायदे के नुकसान होते हैं। इसका इस्तेमाल करते वक्त इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। उस हद तक हम इसकी मदद करना चाहते हैं। मैं जनाब फॉरेन मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि हुर्रियत के साथ आप भी बात करना चाहते हैं और इसकी रिकग्नीशन मुशर्रफ भी करके गये हैं, लेकिन हुर्रियत क्या है? जम्मू में चालीस लाख लोग रहते हैं, जिनमें हिन्दू और मुसलमान दोनों हैं। आपके पास हुर्रियत 25 आदमियों की है। उसमें से एक भी आदमी जम्मू सूबे का नहीं है, एक भी लद्दाख या कारगिल का नहीं है। कश्मीर में प्रिंसिपल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। 80 फीसदी लोग पौनी सदी से इस पार्टी के साथ हैं। इसके बावजूद वहां पर जो 10 परसेंट पाकिस्तान के पाले हुए लोग, पाकिस्तान की तरफ से करोड़ों रुपये देने के बाद जो ये एंटी इंडिया किस्म के लोग हैं, उसमें से ये लोग जो हैं, ये चार बच्चे या चार बूढ़े, यही रीप्रेज़ेंटेशन नहीं करते हैं लेकिन हमारी सरकार इतनी जम्हूरी है कि वहां से जो हुर्रियत के लोग वीज़ा पर आते हैं, उनको ओ.आई.सी. की मीटिंग में मुसलमान मुल्कों में भेजा जाता है। वे वहां पर जाकर रोना रोते हैं। जितना जुल्म वे खुद करते हैं, वह भारत के हक में दर्ज करते हैं और दर्ज करने के बाद करोड़ों रुपया हमदर्दी का ये वापसी पर ले आते हैं। इस सिलसिले में मैं इतना कहूंगा कि मुशर्रफ लाइन ऑफ ऐक्चुअल कंट्रोल को मानते ही नहीं हैं। आइनी तौर पर जो पी.ओ.के. है, वह हमारा हिस्सा है। जो महाराजा हरी सिंह जी ने इलहाक किया है, वह पूरी रियासत का किया है और अगर पूरी रियासत का इलहाक किया है तो वहां पर जाबराना और गासिबाना कब्जा किसका है? पाकिस्तान का है। असूली तौर पर तो कॉन्स्टीट्यूशनली, पॉलिटिकली, मॉरली वह हमारा हिस्सा है और हमने वहां पर 25 नम्बर असैम्बली की सीटें खाली रखी हैं। जिस वक्त ये हिस्सा हम

वापिस लेंगे, वहां 25 एम.एल.ए. जो हैं, उनको इलैक्शन लड़ाएंगे। हमें चाहिए कि आइंदा कोई भी समिट हो, उस समिट में हमारा सबसे पहला कोर ईशू पी.ओ.के., पाकिस्तान आकूपाइड कश्मीर की वापसी का होना चाहिए, उसके बाद टैररिज्म की बात होनी चाहिए। तभी तो बात बनती है, क्योंकि 50 परसेंट हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को दिया हुआ है और उस पर सिल्क रोड बनाई है और वहां से आना-जाना शुरू कर दिया है।

उपसभापति : मिर्जा साहब, अब मंत्री जी को बोलना है। आप पहले खत्म कर लीजिए।

†**मिर्जा अब्दुल रशीद** : मैं अर्ज कर रहा था कि इस सिलसिले में जो पी.ओ.के. का एरिया है, आइन्दा वही हमारा कोर ईशू होना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये पी.ओ.के. का जो हमारा एरिया है, यह कांस्टीट्यूशनली है। पाकिस्तान के जितने भी ट्रेनिंग कैम्प हैं उसने सभी उसी एरिया में रखे हुए हैं। ट्रेनिंग करने के बाद ये सारी तबाही हमारे यहां ही करते हैं। अगर हमारी सरकार भी उस एरिया में जाकर जंग न करे कम से कम थप्पड़ का जवाब थप्पड़ तो दे, टिट फॉर टेट तो करे। उनको यह कहे अरे भाई, तुम करते क्या हो? हम मार खाते रहते हैं, जख्मी होते हैं लेकिन फिर बात करते हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि पैगम्बरों ने और अवतारों ने भी बुराई के खिलाफ जिहाद का हुकम दिया है, लड़ाई का हुकम दिया है। इतनी भी शराफत नहीं होनी चाहिए कि कोई हमको हर लिहाज से खत्म कर दे और हम फिर बात करते रहें। मौलवी साहब ने ठीक कहा कि हम बोली से बात करते हैं और वे गोली से जवाब दे रहे हैं, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए एक गुजारिश करूंगा कि यह जो कांफ्रेंस थी, इससे जो रास्ता खुला है, यह गुफ्तगू बन्द हो और बात चलती रहे। यह बहुत अच्छी बात है। तारीख में यह एक बहुत बड़ा कदम है। जनरल मुशर्रफ इस कांफ्रेंस में बहुत तेज-तर्रार बोल रहे थे। उनके बोलने के पीछे कुछ कट्टरपंथियों और जिहादियों का खौफ भी था। इसके साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि जोर से बोलना हमारी तहजीब नहीं है। हमारे लीडर वाजपेयी जी बड़े मदब्बत सियासतदान और ताहम्मल के साथ बात करते थे, अपने नुक्ते पर बैठे हुए और शोर नहीं करते थे, प्रचार नहीं करते थे। एक शांत समुद्र की तरह बात करते थे इसीलिए उन्होंने खाली हाथ उन्हें वापस किया और यह भी सच है कि सर्द लोहा काट देता है गर्म फौलाद को। उनके हक में मैं यह कहना चाहता हूं कि सौर-ए-दरिया से समुद्र का सपूत जितना जिसका गरफ है, यह इतना ही खामोश है। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा जनाब जसवंत सिंह साहब से एटोनोमी को रिस्टोर करने के सिलसिले में इस हाउस में एक कमेटी बनाई जाए। जो नुक्ता आज ओब्जेक्शनेबल है, उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन आज इसको रद्द नहीं कर सकते, इन्कार नहीं कर सकते। यह सबसे बड़ी बात है। दूसरे आपका कोर ईशू पी.ओ.के. का होना चाहिए और इसके बाद टेरेरिज्म और दूसरे ईशू होने चाहिए। क्योंकि हक तो आपका है। यह रियासत हमारी है। महाराजा ने उसको इलाहक किया है। उन्होंने तो इलाहक भी नहीं किया। इसी इंडिपेंडेंट एक्ट से ब्रतीनी हुकूमत ने पास किया था और उसी से दो मुल्क बने। जो 505 रियासतें थी, वे इस मुल्क और उस मुल्क का हिस्सा बनीं। उसी एक्ट के अनुसार महाराजा हरिसिंह ने जिन्हें उस मुल्क का साथ शेरे कश्मीर मिला हुआ है, सपोर्ट की हुई है। मैं इतना

---

† Transliteration of the speech in Persian Script is available in the Hindi version of the debate.

कहते हुए इसकी ताईद करता हूं और यह चाहता हूं कि यह जो दरवाजा, रास्ता खुला है यह कायम रहे। गुफ्तगू बन्द न हो बात से बात चलती रहे।

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS AND THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JASWANT SINGH): Madam Deputy Chairman, above all, mindful of the fact that the Summit itself having taken place in mid-July, I made as extensive a statement on behalf of the Government, as I could mindful of the fact that within a week thereof, the Parliament was meeting on 17th of July. Thereafter, on the very first occasion, the hon. Prime Minister made a statement in the House -- if you recollect, the House had been adjourned on 23rd July due to condolences -- on the 24th of July itself. Since 24th of July, in one House or the other House, this issue has been under discussion. It is now almost three weeks that we have been engaged in examining the Agra Summit in all its ramifications. Most of what there had to be said, has already been said, commented upon and analysed. There is a phrase which is quite catching that we can engage in an analysis that carries us forward to paralysis. Without attempting to do so, I will endeavour, as best as I can, to answer the substantial issues, the fundamentals also, and address myself to the points of criticism that the hon. Members, during their observations have made about the conduct of the Government or the approach of the Government. However, Before I do so, Madam, there are some haphazard observations that, I think, is my duty and function to address. Dr. Manmohan Singh opened the discussion as the Leader of the Opposition. I was very struck, Madam, by the manner, by the words of approbation he had for the visiting dignitary and his conduct, and equally strong words of condemnation that he chose to employ for me, as also for the Government on the conduct of the Agra Summit as also on the larger conduct of foreign policy. I was struck and without taking to much time, I do wish to share, I do wish to remind the hon. House, that the distinguished and learned Dr. Manmohan Singh in his intervention, used these words of approbation for the visiting dignitary, amongst others, 'single minded', 'purposeful', 'ruthless clarity', 'skilfully', 'not naive or frivolous', 'master of media arrangement', 'highly skilful' and 'even to hijack the agenda'. This is a very generous praise indeed. I have no doubt in my mind with his characteristic generosity and large heartedness when he chose to so describe the visiting dignitary, surely, it could not have been only on account of the fleeting meetings that he might have had with him or what he has read -- But I have no doubt that despite what he has read of him, this equity of his perception and his mind, the phraseology that he chose, he chose this is how the visiting dignitary is best assessed.

However, by whatever method he has arrived at this assessment, I do beg to differ and I beg to differ on the fundamentals, particularly when I see, when I reflect on the severity of his observations against my conduct of the country's foreign policy during the last two or three years -- he specified during the last two or three years -- and the phraseology that he has employed to condemn me on the conduct of the foreign policy, I was struck by the contrast. I do not have to repeat the eulogies that he heaped on General Pervez Musharraf. I have applied myself and addressed myself to the criticism that the learned, the Leader of the Opposition made because he charged me, Madam, with an absence of studied application of mind, long-term thinking, I have not the attitude or the mental equity of the Leader of Opposition, but to charge me with an absence of studied application of mind is very severe criticism, and he said, because of me there is no long term underpinning to country's foreign policy, and he cited some instances. I can very easily elaborate on the instances.

He said, "I lack conceptual clarity"; not just conceptual clarity, but I have no clarity about our immediate objectives. And, of course, inadequate preparation; again, I am devoid of a clear thinking. There seems to be a great deal of confusion in my mind. But the basic confusion, as the Leader of the Opposition calls it, is about our objectives, and he charges me and the Government with lack of pro-active diplomacy. It is not for you or for me to score any debating points. These are substantial issues. And these are substantial charges. It is my duty to address them, very briefly, as best as I can.

On the question of long-term under-pinning, studied application of mind, conceptual clarity it is roughly the same thing, in one fashion or the other may I, with due regard to the learning of the Leader of the Opposition, submit to him for consideration that, in major foreign policy challenges, problems or issues that the country today confronts are a legacy, principally, primarily, of the successive Congress Governments, starting from the invasion of Jammu and Kashmir in 1947-48? It is not for me to remind Dr. Manmohan Singh that this legacy continues. Who did what in which year? Because, Dr. Manmohan Singh also charged that we lack an approach on Jammu and Kashmir. May I remind the learned Leader of the Opposition that, when he was a Member of the Cabinet, the incidents at Dargah Hazratbal or the burning down of Charar-e-Sharief took place? These are also incidents. These are challenges to India which I have and occasion to point out and I had written about them. In the three principal foreign policy

challenges, Jammu and Kashmir, Sino-Indian border dispute, IPKF, we do believe, these were great errors of conceptual clarity that have resulted in the country, and successive generations of the country, having to deal with these issues. I have said so, on a number of earlier occasions, that it is possible to address the issues relating to internal management of the polity of the country in a reasonably short-time frame. But errors on foreign policy afflict the successive generations to handle. And, if there are examples to be seen, these examples are really best illustrated by what the country has had to do for the past fifty years in the case of Jammu and Kashmir, what the country has had to do from the mid-fifties in the case of China-India relationship and, of course, I continue to believe that the IPKF was a great mistake that not simply cost us the lives of our own soldiers, but it is the only instance when we had to bring back our forces. However, let that pass; because we continue to dwell upon the mistakes of each other. The challenges of today are very grave. The Leader of the Opposition, I have no doubt in my mind, has exercised his wisdom and his learning in approbation in the words of praise that he has used for the visiting dignitary.

And I take seriously the words of criticism that he has used against me. I will address, Madam, as best as I can, and as God has given me the ability to assess afresh, and I have, since he used these phrases, attempted to do so. I am unable to convince myself that I lack application of mind -- I might lack in other aspects; I do not have his great learning; but, so far as application of mind is concerned, I do try and apply my mind; that I do not have too much mind, is possible; but about application ...*(Interruptions)*...

I will come to the substantial issues about preparation, agenda and all other aspects in a minute. These are the other peripheral issues. I regret very much that I was not here because Dr. Karan Singh, in his intervention, said, "The Minister is not here. I trust he is listening to what I have to say, on the television". He had some kind words to say. But he said that I made an error in announcing the DGMO's visit. Now, I had, Madam, then submitted a request, both to the Chair as also to the Leader of the Opposition, that a meeting had been called on Jammu and Kashmir by the Home Minister, where I was required to be present. And I hadn't withdrawn to my chamber to watch as substantial and meaningful an intervention as that of Dr. Karan Singh, who said that he was a part of history. Indeed, he had been the Maharaja of Kashmir. And when he intervenes, it is my duty to be present here. But, as far as the Director General of Military Operations is concerned, there were three

announcements made unilaterally by the Government on the 4th of July, on the 6th of July and on the 9th of July. The announcement of the 4th of July related substantially to aspects that Shri Kuldip Nayyar referred to, about enabling people to people contacts, trade and commerce. So, we said, "Students can come; scholarships are offered, easier visas so that there is people-to-people contact. Fifty lines were to be identified by commerce. Fishermen were to be released. Also that, in future, the Coast Guard would have instructions, when fishermen so transgress. Similarly, on the 6th of July, we announced that the DGMO would seek the convenience of his counterpart and visit Pakistan so that we can move forward on the gains that we have made, so far as the relative stability on the Line of Control is concerned. Plus, we will initiate actions in regard to confidence building measures about nuclear issues. This was on the 6th. And, on the 9th of July, it was the opening of Srinagar-Muzaffarabad-Attari, also Manabu, again people-to-people related. Now, it is not, as Dr. Karan Singh says, that I had instructed the Director General of Military Operations to go the next day. I had said, normally, they confer with each other on the telephone on Tuesday, and when the announcement was made, the talk was due to take place the next day, and that they will talk to each other the next day. Well, the rest is now history. Pakistan did not respond positively to it. We have announced that these measures that we had taken remain in position and we will continue to move forward on these measures. Whenever we can implement them unilaterally, we will do so. But when we need Pakistan to cooperate with us, it is our expectation that they will do so. Now, I wish to take up an issue relating to what Shri Kapil Sibal and also Shri Janeshwar Mishraji mentioned. That is about foreign hand and third party intervention.

Mr. Sibal averred that there was a foreign hand; that this initiative has been taken on account of pressures from the United States of America. Then, he cited a statement and also the chronology of the dates. I do wish to submit, Madam, --and I have said so earlier too --- and I say this with a certain degree of trepidation because very eminent jurists and practitioners of law are Members of this House -- the Houses of Legislatures are not court of law. When hon. Members who practice law as a vocation or profession, benefit us with their views in the Chambers of the Legislature, with great humility, I submit to them that it is best not to put across a case as if a legal brief is being argued. This is essentially a House, the main purpose of which is, of course, political and other aspects. So, Mr. Sibal cited a statement made by the Spokesman of the White House on June, 18, and said 'before the formal announcement was made, the Prime Minister,

when asked on 19th, had said such and such, the Spokesman had said such and such; therefore, as in a criminal law court he said 'you are guilty, and you acted under so and so's pressures.' Let me please clarify, the question that was put to Mr. Fisher was -- at that time, the Foreign Minister of Pakistan, my distinguished counterpart, Mr. Sattar; was in Washington -- and this question was put to Mr. Fisher --he is here meeting with Ambassador Condoleeza Rice, and if the President is planning to drop by -- and the record here says (Laughter from the Press) -- is the Foreign Minister of India planning to drop by; and also, how much role the President is playing in the upcoming summit between India and Pakistan? No, of course, because, yet again I did not know that it is a standard practice for lawyers to engage in suppressio veri and suggestio falsi ...*(Interruptions)*...

SHRI RAM JETHMALANI (Maharashtra) : Madam, I wish to protest this. My friend can settle his scores with Mr. Kapil Sibal but please don't disgrace lawyers..*(Interruptions)*...

SHRI JASWANT SINGH: I am not disgracing lawyers..*(Interruptions)*... Madam, he is a distinguished jurist.

SHRI RAM JETHMALANI: I do not bother whether I am a distinguished jurist or not ...*(Interruptions)*... but don't disgrace the profession..*(Interruptions)*...

SHRI JASWANT SINGH: No, I don't. Now, here is what was said. My distinguished counterpart, the Foreign Minister of Pakistan, was in Washington, and was due to meet me shortly. Please also remember it was June 18 and Washington's time is ten-and-a-half hours behind the Indian time. So, Mr. Fisher said, first of all, the meeting has not yet taken place; that the meeting between Condoleeza Rice and Sattar was to be held in the afternoon. Afternoon in Washington means evening in India 18th. And, if there are any drop- bys, I will do my best to let you know that the Administration is committed to building a mutually beneficiai bilateral relationship with Pakistan. The Administration is looking forward to a return to democracy that will permit fully normalised relations and the United States of America fully supports the upcoming 14th July meeting between India and Pakistan. Now, the whole thesis that was built by the hon. Shri Kapil Sibal was because the US Spokesman said on June 18th that July 14th is the meeting; therefore, India acted under the pressures of United States of America, because the formal date had not yet been announced.

Let me please clarify, Madam, that there were two sets of dates that were under consideration, *i.e.*, 7th to 9th of July -- because those two windows had been suggested and 14th to 16th of July. I had let it be known that these are the windows, and, Pakistan, of course, knew that these are the two windows that have been spoken of. Shri Kapil Sibal also said that during this period I was as he graphically put it flying between Delhi and Washington, as indeed was the Principal Secretary and the National Security Advisor. I was not actually there. I was, in fact, in Australia during those dates which have been mentioned, which is quite far, geographically, from here, and, otherwise, from United States of America. Before I went to Australia, I had let it be known that the proposed dates can be and will be finalised only after I had called on the Prime Minister, who was then convalescing in Mumbai. The doctors had said that he would be operated on the 7th of June. The doctors had advised that, at least, for one month, he is not to move. They said, "If you can avoid it, don't have the Summit meeting on 7th of July." However, I did not wish to confirm about the non-availability of those window of dates, until I had a chance to go and meet the Prime Minister myself. I did not go and meet the Prime Minister then. On the 7th of June, he was operated on. In the first week itself, Madam, it was very difficult to go and trouble him about such issues. It was a major surgery that he had undergone. I, therefore, visited Mumbai, to call on the Prime Minister, and discussed these issues with him only on the 15th of June. However, the proposed dates, *i.e.*, 7th to 9th of July, as already cleared, would be very difficult to adhere to. I returned on the 16th. Pakistan was formally informed of the dates that were proposed, *i.e*, 14th, 15th and 16th of July, on the 16th of June itself. On 16th of June, Pakistan was formally informed. And on 18th of June, Pakistan's High Commissioner confirmed that these dates of 14th to 16th July were convenient. On 18th of June, Mr. Abdus Sattar was in Washington. No doubt, the High Commissioner here and the Pakistan Foreign office in Islamabad knew about it. Though, of course, they did not, in other regards, had the same communication with their Foreign Minister, but in this regard, they certainly had the communication. They informed him that the dates that are being spoken of are 14th July. Before this meeting with Condoleeza Rice, Mr. Abdus Sattar had already had his meeting with Mr. Colin Powell. So, the dates of 14th July to 16th July, which we formally announced on 18th or, perhaps, on 19th, were formally announced by Pakistan in Islamabad, and were known to their Foreign Minister in Washington. There is no great mystery, there is certainly no third hand in it, there is not any third party in

2.00 P.M.

it, and certainly there is no foreign hand in it. This Government, this Prime Minister, certainly requires the proving of no credentials, Madam, when it comes to not cleaving to any kind of foreign pressure, be it the United States of America or any other country. The entire history of post-May, 1998 till now, *i.e.*, July, 2001, if nothing else, exemplifies that it is not under pressure that we worked. Madam, there were two other points. Mr. Sibal has made one other observation, and the same observation was made by some other hon. Member.

One more observation was made by Mr. Sibal. This observation was also made by some other hon. Members. He said, "whereas the spokesman of the Ministry of External Affairs on 16th spoke of disappointment, the Minister said: No, we are not disappointed with this meeting." I do not know how he worked out these two together. Here is what my Joint Secretary (External Publicity) said on 16th: "I am disappointed to inform you, ladies and gentlemen of the media, that though the commencement of the process and a beginning on the journey has taken place, the destination of an agreed joint statement has not been reached. It is now very late and I do not wish to go into any detailed elaboration. We would be holding a fulifledged Press conference at this very venue at 10 hours tomorrow morning." So, the disappointment which the Joint Secretary expressed was about the absence of an agreed document.

I cannot recall whether I said the same thing on the 17th. But, on a subsequent date -- it must be two or three days later at a Hindi interview मुझ से पूछा गया। मैंने कहा मैं डिस-अपाइंटेड हूं कि किसी करार पर दस्तखत नहीं हुए। तो उन्होंने हिंदी में उसको सम-अप करते हुए कहा कि, 'विदेश मंत्री ने कहा कि वह निराश हैं।' मुझे अभी तक याद आता है, मैं ने कहा कि मैं निराश नहीं हूं, मैं डिस-अपॉइंटेड हूं और हिंदी में डिस-अपाइंटेड का मुझे न उस वक्त कोई शब्द ध्यान आया और न आज तक समझ पाया हूं कि डिस-अपांटेड का सही शब्द हिंदी में क्या है।

I will come to other issues in a minute.

About cross-border terrorism, Mr. Sibal spent a great deal of time in legalistic hair-splitting that it cannot be cross-border terrorism, because it is cross-LoC; and LoC is not a border etc. etc. Of course, I know it is not a border. We have always called it 'cross-border terrorism'. But, I do not know if the hon. Member, Shri Sibal realises that he has actually given voice to an argument that has been given by the Foreign Minister of Pakistan. I reject this notion totally that simply on legalistic hair-splitting, since LoC is

not border, therefore, what is it that the Government is talking about. I am sure, Mr. Sibal was not inspired by what my distinguished counterpart, Mr. Sattar had said. But I do appeal to him that, in the enthusiasm for legalistic hair-splitting, this kind of an approach does not help in dealing with the menace that we face collectively.

I do wish to address very briefly जो शरीक साहब ने बताया about autonomy, about Pak occupied Kashmir. हमारे वजीरे आज़म साहब ने जब मुशर्रफ साहब से बात की तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि आप जम्मू-कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच का कोर इश्यू समझते हैं, लेकिन मुझे कोर की कोर में जाना होगा और मुझे आप को साफ बताना होगा कि यह जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वह चाहे हुंजा हो, चाहे चितराल हो, चाहे गिलगिट हो, चाहे शख्सगाम वैली हो, जो आप चीन को दे चुके हैं, वहां आप गलत बैठे हैं।

THE LEADER OF THE OPPOSITION (DR. MANMOHAN SINGH): Chakral has never been a part of Jammu and Kashmir.

SHRI JASWANT SINGH: It is a northern area. But it was also wrongly occupied. And the Shakhasgam Valley. These were clearly pointed out to Gen. Parvez Musharraf कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में, जिस की 25 सीटें हमारी एसेंबली में खाली रहती हैं, कोई शक-शुबहा नहीं होना चाहिए।

SHRI SHARIEF-UD-DIN SHARIQ (Jammu and Kashmir) : Their High Court has set it aside.

श्री जसवंत सिंह : जी हां, उनके हाईकोर्ट ने भी कहा है नॉदर्न एरियाज पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं। अब वह इस तरह कहने लगे फिर तो बहुत लंबी तवारीख में जाना होगा। अटल जी ने कहा कि आप इस मसले को लेते हैं तो मुझे भी इस की बात साफ करनी होगी। दूसरी बात आपने ऐटॉनमी की फरमाई जम्मू-कश्मीर की। कल होम मिनिस्टर साहब यहां इस बारे में कह चुके हैं। मेरे पास तो अधिकार नहीं कि मैं होम मिनिस्टर साहब का जो क्षेत्र है, जो उनका अधिकार क्षेत्र है, उसके बारे में कुछ कहूं, पर इतना जरूर वह कह चुके हैं कि धारा 370 से पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं है। ऐटॉनमी के बारे में उन्होंने कहा कि सरकारिया कमीशन दूसरे राज्यों पर लागू हो सकता है, उसमें काम-काज चल रहा है, जम्मू-कश्मीर का एक विशेष दर्जा है, इसलिए हमें सरकारिया कमीशन से आगे चलकर ऐटॉनामी के बारे में बात करनी होगी। I have no doubt in my mind that the Home Minister and the Cabinet will be addressing this issue.

Sir, I must very briefly, because I have said so in the other House and I do not wish to tax the patience of the hon. Members who, on a Friday afternoon have honoured me by being here. But on India and Pakistan long-term relationship I have said so in the United Nations General Assembly. I have said so in public. I have said so in print, not simply in

some of my speeches, I have said that what Pakistan has to come to terms with and decide is what kind of long-term relationship it wants with India.

What do I mean by Pakistan having to come to terms on what kind of long-term relationship does it want with India, Madam, it is clear, the Government is clear in its mind, that Pakistan has adopted, continues to pursue and practise a position of compulsive and perpetual hostility to India because India's concept of nationhood is the very anti-thesis of what Pakistan is attempting to build as its nationhood. I have said, we stand for civic nationalism; the fundamental of civic nationalism is, irrespective of your faith, your calling, your caste, your creed or colour, it is civic nationalism which inspires India's nationalism. Secularism is the root of it. The Prime Minister has said so many times सैकुलारेज्म तो हमको जन्म में घुट्टी के तौर पर मिला है। We don't have to learn propound secularism, or, the propounded secularism. On the other hand, Pakistan pursues compulsive hostility and perpetual hostility, because it has adopted the two nation theory which we cannot accept. It has adopted it as a means of building and keeping its nationhood alive. This hostility, two nations हिन्दू-मुसलमान अलग-अलग हैं, मैंने कहा था, कई बार कह चुका हूं। आप जम्मू-कश्मीर में कश्मीर की वादी, the Valley of Srinagar, you claim because in the Valley of Srinagar reside my citizens who subscribe to the noble faith of Islam and the percentage of population is 85 per cent, 90 per cent. I will cite you instances of districts in India, in other parts of India, where too, my citizens have similar population, whether it is Rampur or in Tamil Nadu or in Kerala or in Bihar, and what am I to do? And I said this at Agra. What should I do with those districts? Should I put all those districts on a railway rack and send them by train to Pakistan? How am I to accept it? I am not able to accept it.

This is the fundamental fracture. This fracture can be repaired only if we enable the people of India and the people of Pakistan to relate to each other. There are millions whose relatives live across the border. Till today, my relatives continue to live in Sind. There are millions of citizens of Pakistan whose relatives continue to live here. Mr. Kuldip Nayyar spoke of people. I believe it will take time. The more the people are able to relate to each other, सरहद खोलने के पीछे क्या मंशा है? आएं लोग मिलें एक दूसरे से, आने दीजिए। जो पाकिस्तान के गलत कब्जे में जम्मू-कश्मीर का हिस्सा है, वहां से लोग आकर देखें तो सही।

I have no difficulty in sharing an experience of mine, within a minute. A friend of mine had some visitor from Pakistan. There was a young, newly married, girl from Pakistan who came to visit some of her relatives in Bombay. She was staying with the friend of mine. As Bombay girls would do, early in the morning, she put on her jogging shorts and

jogging shoes and went out on Marine Drive or wherever, to have a morning jog. She asked the friend of mine, "अरे, खालाजान, आप कर क्या रही हैं? आप ऐसी छोटी-छोटी निकर पहनकर सड़क पर दौड़ रही हैं "! उन्होंने कहा कि "अरे, इसमें क्या है, Why are you astonished?"तब उसने कहा कि "हम तो ख्वाब देखते हैं कि ऐसा हम कर सकें "।

I do believe, I have often said so. Madam, I have said so in public meetings. India, Pakistan and Bangladesh are of the same womb. How much closer can you be? You cannot be enemies. वे एक ही कोख के जन्मे हैं लेकिन Persuasion in Pakistan is नहीं, हम एक कोख के नहीं हैं।

The Foreign Minister of Pakistan once said, "The problem is with Punjabi." I beg a pardon. Either the Leader of the Opposition or the distinguished journalist, Mr. Kuldip Nayyar, may find fault with the Foreign Minister. He said, "I do want Pakistan to belong to Arabia, but what am I to do with the Punjabi language?". This is what he said. This is the fundamental. How can this fundamental be gapped? This fundamental can only be gapped over time. This fundamental can only be gapped with patience. I am very clear about two approaches, both of which the Government is trying. You challenge India militarily; and that challenge will not only be met, it will be defeated and it will be done time and again. But we bear no enmity to the people of Pakistan. I have said this also in public meetings. What do we desire? We covet not one inch of Pakistan's territory. We have, by God's Grace, enough issues to deal with. We do not want issues to be exported from Pakistan to India. We want a politically-at-ease Pakistan. No matter how you decide your internal arrangement, we would like you to be democratic. But we cannot dictate what you should do yourselves. If, socially, it is a Pakistan that is not torn within, an economically viable Pakistan, it is good for Pakistan, it is good for Indo-Pak relations, it is good for the region. But we cannot do it for Pakistan. What we can do, we do to the maximum. Therefore, we will continue to do it. On Jammu and Kashmir, let me make it, again, very clear, Jammu and Kashmir is not a territorial dispute.

It is a mistake. After all, why does Pakistan not speak if it is a territorial dispute of a substantial value or that 38,000 square kms area of Ladhak is under the occupation of the Peoples' Republic of China? We address that issue separately. We are dealing with that. We have been raising our concern that it is not a territorial dispute. It is a dispute over fundamentals, fundamentals that I have just mentioned. The Government is very clear in this regard. That is why Jammu and Kashmir is not a cause of any dispute between India and Pakistan. It is a consequence, and it is a

consequence of that mentality. I am convinced by mind that it is not a cause, it is a consequence. The corrective is in the correction of the approach towards India--two-nation theory. Otherwise, Pakistan, elements within Pakistan contribute. This is how we approach the problem. There is no ambiguity whatsoever in this regard. Madam, I find that I am taking too long. I must hurry up. Now, I come to cross-border terrorism. There is no compromise with cross-border terrorism. Why do we keep on emphasising cross-border terrorism? India will simply not accept the conferring upon cross-border terrorism the kind of legitimacy or a kind of status that terrorism, as a pre-dialogue negotiating tactics, to be employed by Pakistan. In regard to pre-dialogue negotiating tactics, I will turn the tap of terrorism on until you come and sit with me, and if I find that the progress of the dialogue is satisfactory, then I will turn the tap of terrorism down or turn it up the minute in fundamentals, I accept or agree to confer upon cross-border terrorism this kind of legitimacy or status, as a pre-dialogue negotiating tool or tactics, and compromising with fundamentals. The Government is very clear about it. If the hon. Members recollect, on the 11th of June, 1999, on the eve of the visit of the then Foreign Minister of Pakistan, Sartaj Aziz, I had said before the Press: "We ask Pakistan to vacate the aggression, we ask Pakistan to reaffirm the validity of the Line of Control, abandon hostile propaganda and give up cross-border terrorism." From June 1999, deliberately, and with great sense of purpose, the Government undertook an international campaign to put cross-border terrorism on the agenda of international conferences. I do believe that we have not failed in that regard, and today, the international consciousness in regard to this kind of terrorism, is much more than ever before. That is why we continue to emphasise that there will be no compromise with them. There cannot be. You are not compromising with violence. You are compromising with fundamentals, and there is no way that any Government can compromise with this, leave alone this kind of a thing. These are some of the fundamentals that I am stating. On Shimla and Lahore, it was mentioned that, on the 17th of July, when I addressed the Press in Agra, I said that we will carry forward the process. Two days later, the spokesman of the Ministry of External Affairs said, the foundation is still in Shimla and Lahore. Therefore, we are not speaking in dissonant or separate voices. We are not. It is very clear, Madam, that we attempted to discuss anything, and we discussed anything, and I will come in a moment to this point and give the chronology of how developments took place. You cannot, like as I have said in the other House, confer upon an agreement that was not

reached or the discussions about that agreement the status, as a document, that we subscribe to or is inscribed by signatories.

Yes, there are some gains, but gains do not replace the foundations of bilateralism, which is Shimla and Lahore. Therefore, Shimla and Lahore can simply not be replaced by understandings reached in Agra. Understandings, by their very nature, can be subjectively interpreted, selectively interpreted. Therefore, you always have to go back to the fundamentals. Therefore, the Shimla and Lahore understandings will provide us some help, and help to continue the dialogue process.

I have broadly four points of criticism. One was, there was inadequate preparation. You know, Madam, what I have to say about this particular aspect. Secondly, my good friends in the Opposition have decided that this is a stick to beat the Government with. Fine. The third is about the media. And the fourth was whether Agra has to be called a success or a failure.

Let me start with the fourth point because, then, it is easier for me to put in place the other three. The success or failure of Agra should not be judged against the criteria of a catalyst of the agreed document. Of course, had there been an agreed document, then Agra would have been a success. That could be the assumption. So, we assessed the Agra Summit in the absence of a document! If there had been a document, then all the points about the preparations, the agenda and the media would not have arisen. Why was there not a document? Because, we were unable to bridge the gaps on these two fundamentals on Jammu and Kashmir, and on cross-border terrorism. In the absence of those fundamentals, a document could not be reached. There were also difficulties from the Pakistan side about Shimla and Lahore. In the absence of these three fundamentals, which I have earlier addressed myself to, how was the Government going to address or subscribe to any document? Very briefly, the chronology--I know I am pressed for time--14th is spent in ceremonials here. We had suggested that instead of Delhi we should meet in Goa. From the Pakistan side, a request came, "No, no, no. For a little while, at least, let me come to Delhi!" So, it was proposed that on 14th, the visiting dignitary, the Head of a State, had to arrive; we would receive him ceremoniously, have lunch with our President, and we would withdraw to be at Agra. Then the second request came saying, "Please let me spend a night in Delhi." It is not easy for the host to keep saying ऐसा मत कीजिए The 14th went in ceremonial; 15th, we started working, I think, at 11 o'clock, if I recollect right. 15th, at 11 o'clock, once the work started, there was to be a plenary. The plenary took place, the one to

one went on longer. At the plenary, the Prime Minister read out from a prepared text which covered all these issues. The visiting dignitary spoke from *ad hoc* notes that he had made in pencil. I am not revealing any awkward State secrets. I do believe that the Pakistan delegation really did not know what their leader wanted to do. The full delegation was not aware of what actually was required. Therefore, all the 15th, before everybody rose for lunch, I proposed that a joint statement be issued to the Press for that day. It was suggested that I wrote many things with my pencil in hand. I tell you that on a number of pages there must be my pencil observations.

This is part of the job of drafting, but not always. But when you come across awkward drafting, there is a tendency to do so. I did it and, in fact, suggested that these two or three lines should be issued by both the sides. That was the statement of the 15th. Thereafter, there was no such thing. It was agreed that the two delegations would meet and work on the possibilities of a joint declaration or a joint statement. The Indian team of officials, after the plenary ended--I think it was at 2.30 p.m. or so--suggested to the Pakistan Officials, "Let us meet straightaway, instead of wasting time over lunch because in the evening there is a visit to Taj Mahal and there is a banquet in the evening". There was only a gap of one hour when these two Heads of Governments were to meet again. I state, with due sense of responsibility, that the Pak officials declined to meet because they had no clear instructions. We had an alternative draft, if this was not acceptable, if this was not right, if there had to be a declaration or a joint Press statement or just a joint statement, completely unaligned and bland to substantial issues like a declaration, the Pak Officials said, "We have no clear instructions. We have not prepared any document and we cannot meet". The meeting finally took place only at 11 o'clock in the night, after the banquet, on 15th. The officials and others, who were assisting the Foreign Ministers, had worked about till 4.30 in the morning and produced a document with six square brackets, which were brackets of disagreement. The Heads of Governments had agreed to meet on 16th in the night at 10.30 or so. The scheduled departure of General Pervez Musharraf was at 2.30 p.m. He was to fly from Agra to Jaipur, from Jaipur to Ajmer, to visit Dargah Sharief and Gharib Nawaz. He knew that there was lunch in between; and, between 10.30 and lunch, there was only two-and-a-half hours. General Musharraf then engaged in an exercise of drafting, with our Prime Minister, which is never done. The Heads of Governments sat down and they, perhaps, addressed themselves to substantial issues. Anyway, the rest is now history.

जनरल साहब दरगाह शरीफ नहीं जा सके, किसी ने मुझे कहा कि आप आढ़े फिरे। अरे, मैं कोई आढ़े नहीं रहा जनाब, मेरी क्या औकात कि कोई अजमेर की दरगाह शरीफ जाना चाहे और मैं उसे वहां जाने से रोकूं। मैं यह भी जानता हूं कि बचपन से उसी अजमेर की दरगाह शरीफ में मैं बार-बार माथा टेकने गया हूं। पर अगर गरीब नवाज़ के घर पर जाने का हुकुम नहीं होगा तो कैसे जाएंगे? नहीं हुआ। 16 तारीख हो गयी। दिन भर यह कोशिश हुई। फाइनली 16 तारीख की शाम को जनरल साहब तशरीफ लाए। फेयरवैल कॉन्फ्रेंस थी, 10-15 मिनट के लिए बैठना था लेकिन 80 मिनट तक फिर बात चली। यही मसला था। हमने कहा कि यह मंजूर नहीं होगा, आप आगे बढ़िए।

As regards the preparation, the agenda, there were four sets of agenda. The Shimla Agreement provides the agenda; the Lahore Declaration provides the agenda; the composite dialogue provides the agenda. We proposed all these, plus, in writing, sent an agenda. But the visiting Head of State said, "I will deal with the Head of Government and prepare an agenda myself". हमें मालूम था, इस रास्ते नहीं.. That is why I am saying, "Yes", and I said". My distinguished and gallant friend, Gen. Shankar Roy Chowdhury is here. When General Pervez Musharraf was often given to lauding his military directness, I did suggest to him, "We are not entirely absent of military virtues either".

But there is a fine dividing line between military directness and military simplicism. In this complexity of issues that diplomacy has often to address in Jammu and Kashmir talking about Indo-Pak relations and talking of simple issues. We are talking of complex issues involving people's sentiments. That is why when the Prime Minister had gone to Lahore, he used a phrase that is etched in my memory, यह बस लोहे और इस्पात की बस नहीं है यह जजबात की बस है। You are addressing issues that are not simply legalistic issues. जनरल साहब फरमाने लगे कि स्टेटमेंट क्या चीज होती है, और बाद में इस्लामाबाद में जाकर फरमाया, "स्टेटमेंट क्या चीज होती है। It is after all an exercise in English composition. मैं आधे घंटे में बना देता हूं।" हो सकता है वह आधे घंटे में बना सकते। ऐसे मसले आधे घंटे में कागजों में हल नहीं हो सकते। On media, I continue to hold that the difficulty begins to arrive on 16th. I can understand that. I had the difficulty. The Joint Secretary (External Publicity) and other officers had met... ...*(Interruptions)*... बस दो, तीन मिनट में खत्म करता हूं। Could we have addressed this differently on the 16th? I was engaged personally as were my officers. I have explained the compression of time that had taken place on the 16th. I have tried to explain how much we wanted out of this Agra Summit for the sake of addressing the principal challenge that India and Pakistan have, *i.e.* poverty. Let there be a forward movement. I was certainly addressing myself to finding a way out that, after all, is my job. My

job is to bridge the gaps of perception. My job is to try and arrive at a position that we can both subscribe to. I should have paid more attention to media management. Who is responsible for not paying that attention? I am responsible. If anybody is to be charged with any fault, I am to be charged with that fault. I do accept my responsibility. I have learnt and I continue to hold that issues of high importance cannot be discussed through media no matter how much the media may like to play a role not simply in formulating, in practising, in influencing policy outcomes of complex negotiations. It is not possible. it is simply not possible to do so. I recognise that we live in a world of instant communication far different than earlier instant communication, particularly the visual media. I have had something to do not with media but certainly with information technology and other issues. The visual media demands, when there are 24 hour news channels, news after every two minutes and ten minutes. Complex issues you cannot convert into every ten minutes or two minutes news. Yet this needs to be met because visual media goes into everyone's bedroom. Print media is tomorrow's news. Instant visual media is instant news. The demand was for instant news. That, I expect, was their priority. My priority was somehow to try and bridge the gap and find a position where I could reach an agreement. In the process I failed to fulfil the expectations of the media. If anyone is responsible, I alone am responsible. But I cannot use Pakistan as an example of how to conduct diplomacy. The breakfast meeting by Gen. Musharraf has been cited as an example of what Atalji should have done.

It is not for me to advise the Prime Minister, though I can advise my Cabinet colleagues. But I don't think, I am persuaded that that is a matter which India should follow simply because Pakistan had followed it. We will not use Pakistan as some kind of a yardstick by which we either judge our own methods or alter our own methods. Madam, the path ahead is quite clear to us. We will continue to approach the issue, the India-Pakistan relations, on the broadest possible front, through people-to-people dialogue, commerce, trade, culture, in totality of the relationship, including complex issues like nuclear, military and other interests. We cannot become uni-focal like the good General, however praiseworthy he may be to some people. We have no ambiguity about the status of Jammu and Kashmir. The hon. Leader of the Opposition said, "I find, that is a good sentiment. But what you say is not understood by the people. You have said that Kashmir is not the core issue." Madam, Kashmir is at the core of any issue, and I said the same thing. I said, "जम्मू-कश्मीर कोई जमीन का टुकड़ा

नहीं है, यह हमारे शरीर का अंग है।" It appears to me, quintessentially, what India stands for, as a civilised nation. We cannot make a difference between the brother in Jammu and Kashmir and the brother in other places -- चाहे पंडित, बौद्ध, शिया, सुन्नी, बकरवाल या गुजर हो सभी भारत के नागरिक हैं।

Madam, as regards CBMs and other things, we will pursue them; SAARC has resumed its process. On dialogue, I can only say that though differences are expressed in this case, a caravan of peace is in motion. We had set it in motion at Lahore. We were interrupted at Kargil. We were interrupted at Kandahar. We were interrupted by the killings, whether at Chattisingpura or at other places. But this caravan will continue. Agra was one of the padavs of this caravan. The caravan of peace will continue, and the dogs of war cannot stop this caravan. Thank you, Madam.

DR. MANMOHAN SINGH: Madam, I would want to know three things which have not been answered by him now. I had raised this question of lack of preparedness, and I seek the indulgence of the hon. Foreign Minister to inform us: "Are there other instances where a summit of this nature has taken place without a structured agenda? In particular, what happened at Lahore? Was the Lahore Summit also a case of a summit without a structured agenda? That is the first question which I would like to ask. The second question that I would like to address to the hon. Minister is this. I know that he did provide a lot of technical assistance to the hon. Foreign Minister of Pakistan to correct his English and, according to various accounts, he and Mr. Abdul Sattar had jointly initialled a draft, and, according to newspapers reports, it was left to Advaniji in the Cabinet Committee on Security to shoot down that draft. I would like to know from the Minister whether there is any truth in this statement, which is widely circulating in the Press? Is there such a draft which the hon. Foreign Minister of India and the Foreign Minister of Pakistan had jointly prepared and which, subsequently, was rejected by the Cabinet Committee on Security? The third question which I have to ask the hon. Minister is with regard to the role of the media. Day-before-yesterday, when the hon. Minister of Information and Broadcasting intervened in the debate, she informed the House that her intervention at Agra was a part of grand strategy of the Government.

I would like to know from the hon. Foreign Minister whether that grand strategy was in accordance with which the hon. Minister of Information and Broadcasting issued a press statement at Agra and to which the delegation of Pakistan took such great offence.

SHRI JASWANT SINGH: I will address all the three briefly, but explicitly, and as candidly as I can. Starting with the third, our distinguished colleague in the Cabinet, and my friend, Sushmaji, as the Minister of Information and Broadcasting, was requested by me, saying that it was a summit between two Governments, Head of Government to Head of Government; it was only appropriate that you find it convenient to be present in Agra and that it is under your overall supervision that the entire visiting media, whether Indian or Pakistani or foreign ...*(Interruptions)*... When she intervened, and I think it was on the 15th, and said something to the Press, now, you can't... यह नहीं कि चित्त भी मेरी और पट्ट भी मेरी। सुषमा जी बोली तो क्यों बोली। क्योंकि पाकिस्तान के स्पोक्समैन जनरल कुरेशी ने शिकायत की। मुझे यह कहते हुए कोई तकलीफ नहीं हो रही है। मैं आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता। सुषमा जी ने इस बारे में संकेत भी दिया था। As we do, a number of newspapers conduct a kind of survey, and a question is posed and some readers answer. So, he kept telling me, "Look here, this is a survey conducted by so and so paper and that paper is saying that 78% of India wants you to talk on Jammu and Kashmir. और आप शिकायत करे जा रहे हैं, मुझे मेरे प्रेस एडवाइजर ने कहा"। Now, this is extreme military simplicity. The question that was posed was in a certain fashion. वह आज तक उसको कह रहे हैं that 78% of India wants you to talk on Jammu and Kakshmir. कुरेशी साहब ने कहा कि सारा मसला गड़बड़ा गया क्योंकि मिनिस्टर ऑफ इन्फार्मेशन और ब्राडकास्टिंग ने इन बातों की चर्चा की और जम्मू-कश्मीर पर बातचीत नहीं हुई। जब हमारे यहां लोग सुनेंगे तो वह बौखला जायेंगे और जनरल साहब के लिए दिक्कतें खड़ी हो जायेंगी और यह कहकर, हमने कहा कि देखिए, ये जो मसले हैं ये रिटिन डाक्युमेंट में हैं। They are part of the official statement of the Head of Government of India at the delegation-level meeting. हमने उसको अभी तक इश्यू नहीं किया only out of deference to... आपका प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट नहीं था पेंसिल से कुछ प्वाइंट्स लिखे थे, एक्सटम्पोर बोले थे और जब तक आपका स्टेटमेंट हमको मिले नहीं, we believe that the two should be issued simultaneously.

With due deference to the Leader of the Opposition, again, I do appeal to you, Sir, pay less heed to what General Quraishi said, and a slightly greater heed to what your colleague in Parliament, the Minister of Information and Broadcasting, said. By all means, take into account what General Quraishi says. But General Quraishi, as the spokesman of Pakistan, is not the authorised version. He will naturally say what Pakistan wants to be said and give the colour that it requires to be given to a particular thing. It was her duty to do so. She did it after consulting me and she, in fact, made it clear to me that आप तो मिलेंगे नहीं क्योंकि आप वहां मशगूल हैं। I do not carry my cell-phone. I do have one. But I use it only to call, never to receive telephone calls. हम उसको कहां लियें फिरें। सुषमा जी की शिकायत थी कि

आपसे मिलना मुश्किल है, बात नहीं कर सकती, बोलना मुझे है प्रेस को। मैं क्या कहूं she is right. इसीलिए मैंने कहा कि यह किस की जिम्मेदारी है। it was my duty. I was not able to.. अब मैं सुषमा जी को हर 15 मिनट में कैसे बता सकता हूं। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। Madam, the Leader of the Opposition said that there was an agreed draft which my distinguished counterpart, the Foreign Minister of Pakistan and I, initialled, and that we worked it out in pencil. Madam, no draft was initialled. The suggestion here is that a full agreed text of an agreement was worked out; and that he and I then initialled it. No. That is the first factual error. As I said, and I have no difficulty in being absolutely candid, there were six square brackets in that document that had got prepared in the evening, really 4.30 in the morning of 16th; and that document went to the two heads of the Government, with a view to eliminating as many of the square brackets as possible. गाड़ी आपकी रुक रही थी, एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है जम्मू-कश्मीर। अब वहां ड्राफ्टिंग शुरू हो गई। जनरल साहब ने कहा कि नहीं, अटल जी के साथ मैं उसको करूंगा। This is again part of the military directive. Admirable trait, when a military issue is to be addressed. But I thought this is really not the way to go about it. So, I proposed आप दोनों इस काम को छोड़ दीजिये। My elder, my distinguished counterpart, Sattar saheb, and I, we will address ourselves. Then, it was about 2.30 in the afternoon. Ajmer is already abandoned, or, postponed. Now, the Foreign Ministers should not be doing it. But we said, अच्छा चलिये लिखते हैं, In the process, one particular square bracket, we attempted to reformulate it in a particular fashion. Mr. Sattar said, "Let me take this reformulation back to Hotel Amar Vilas where the General is staying". Because जनरल साहब अमर विलास में बिराज रहे थे। And this was taking place at Hotel Jaypee Palace. So, he said, "Let me take it back to the General" And I said, "I must take it back to my Cabinet colleagues. I am not autonomous. The General is, perhaps, autonomous. I am not. I must take it back to the Cabinet". It was not the Cabinet Committee on Security. It happened to become. So, because that was the part of the delegation, Mr. Maran, Mr. Yashwant Sinha, Mr. L.K. Advani and the Prime Minister, all of us sat there. I said, "This is what it is". All of us then said, "This will not do. We have to go back to India. The priority is not to find an agreed text. The priority is to find such an agreed text, as meets the acceptance of India, because, without the commitment of India, it is a piece of paper. We are not just working on pieces of paper". मुझे तो कोई अधिकार ही नहीं था कि मैं सरकार की ओर से इनिशियल कर दूं, like lawyers settle a brief. I was not settling a brief. It is a very difficult task when one explains. I must say, it is to the credit of my counterpart, Mr. Sattar. He said, देखिये जसवंत सिंह जी, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं और हैं भी उम्र में बड़े। यह बहुत मुश्किल काम आप और हम कर रहे हैं। हम को

दोनों तरफ से गालियां मिलेंगी। यह सही बात है। वह कहने लगे जब मैं ले कर जाऊंगा तो जनरल साहब क्या कहेंगे, किस बात को ले कर आ गये। मैंने आज तक उनको कहा नहीं। आपने पूछा इसलिए मैंने कहा। ...**(व्यवधान)**...

DR. MANMOHAN SINGH: If you were so convinced that India could never accept such a draft, why did you take it to the Cabinet?

SHRI JASWANT SINGH: I took it to the Cabinet; I was not convinced. Mr. Sattar said, इससे आगे हम चल नहीं सकते I was not convinced. I was trying to move it beyond. So, I said that, faithfully, I will convey this. I was not convinced. Had I been convinced, why would I agree with my Cabinet colleagues and come back and say? यह जो काम हमको करना पड़ता है उसमें हमें दोनों तरफ चलना पड़ता है। आपको कहने के बावजूद ...**(व्यवधान)**... डा. मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं, तुम लेकर क्यों गए। साहब, मेरा तो काम है। वे कह रहे थे कि हम यहां तक आने को तैयार हैं इससे आगे नहीं।

श्री शरीफ-उद्-दीन शरीक : अगर नहीं ले जाते, फिर भी यही होता।

श्री जसवंत सिंह : फिर भी यही होता। आपको ईसप की कहानियां याद हैं। एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। ईसप की कहानियां डाक्टर साहब आप तो जानते हैं। आपकी इजाजत हो तो कहूं। एक गधा, बाप और बेटा चल रहे थे। लोगों ने कहा कैसे बेवकूफ हैं, गधा है और दोनों पैदल चल रहे हैं।

श्री सुरेश पचौरी : महोदया, क्या कहानी में कोई ऐसा शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है जो असंसदीय हो?

श्री जसवंत सिंह : गधा तो जानवर है।

उपसभापति : गधे को ही गधा कहेंगे। सुरेश पचौरी जी, गधे को ही गधा कहा जा रहा है। गधे को इन्सान नहीं बना रहे हैं।

श्री जसवंत सिंह : तो लोगों ने कहा, कैसे बेवकूफ हैं। गधा है और दोनों पैदल चल रहे हैं। तो बाप गधे पर बैठ गया। फिर थोड़ा आगे गए। लोग मिले। कैसा बाप है खुद गधे पर बैठा है और बेटे को पैदल चला रहा है। तो बाप उतर गया, बेटे को बैठा दिया। आगे चले। लोग कहने लगे, यह कैसा बेटा है, बाप को पैदल चला रहा है, खुद गधे पर बैठा है। दोनों बैठ गए। लोग कहने लगे, ये कैसे इन्सान हैं, दोनों बैठे हैं। दोनों उतर गए, गधे को सिर पर रख दिया। अब क्या करें साहब, यह नौकरी ऐसी है।

उपसभापति : फाइनली उसको पानी में फेंक दिया। फाइनली जब उन्होंने सिर पर रखा तो लोगों ने कहा कि बेवकूफ हैं गधे को सिर पर रख रहे हैं तो उन्होंने जाकर उसको पानी में फेंक दिया।

श्री जसवंत सिंह : इसीलिए यह कह रहा हूं कि यह नौकरी ऐसी है। The Final point what Dr. Manmohan Singh wanted to know if there are any examples

of summit having taken place without an agenda and also whether Lahore was such an example. Let me be fair with him, Lahore had been preceded by a meeting on 23rd September in New York between Mian Nawaz Sharief and Prime Minister Vajpayee. There was no agenda fixed. There was a broad agreement that 'we will meet and talk'. I was part of the Lahore process also. But with regard to any summit having taken place without an agenda, yes, very recently the meeting between Putin and Bush.. These are to get acquainted with each other. There are two Heads of States. They do not know each other. President Bush was just got elected. There are millions of such examples. But, Madam, this is not really a lesson on diplomatic history. It is a question that I attempted to answer because my distinguished colleague and a senior Member, the Leader of the Opposition asked, and I have attempted to address, as far as I can, the queries raised by the hon. Members. Thank you very much.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now we have a question before the House. We are well into the time of the Private Members' Business. I was reminded that there is auto-rickshaw strike also. Mr. Virumbi was telling that as the Leader of his Party, he has not moved out since eleven o'clock. I think it is inhuman. If the House so agrees, we can adjourn the House for half-an-hour so that the Members can have a cup of tea. ...*(Interruptions)*... I can also have a cup of tea. ...*(Interruptions)*... I was sitting there and I was asked to come. ...*(Interruptions)*...

श्री संघ प्रिय गौतम : उसके बाद तो कोरम ही नहीं होगा।

उपसभापति : यह तो जिनको इंट्रेस्ट है वे आएंगे।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal) : Madam, we have to adjourn at five o'clock because many Members have to catch their flights. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Do you want to continue to sit? ...*(Interruptions)*... I have no problem. I can ask Sureshji to come to my rescue.

(THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) IN THE CHAIR)

PRIVATE MEMBERS BILLS

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2000

(To amend the Eighth Schedule)

SHRI K.C. KONDAIAH (Karnataka) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.